प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

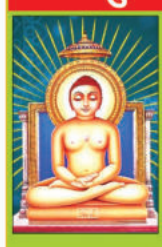

पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम है।
भगवान महावीर

वर्ष-07, अंक - 51 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 18 सितम्बर 2025 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

जीएसटी सुधारः राहत

आम उपभोक्ता को मिले...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

1 जुलाई 2017 से देश में लागू गुड्स एंड सेवा टैक्स यानि जीएसटी को लेकर कांग्रेस शुरू से ही सरकार पर हमलावर रही। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टेक्स बताते रहे, यानि भारी भरकम टैक्स जिस प्रकार शोले फिल्म का खलनायक ग्रामीणों को डरा-धमका कर अधिक टैक्स लेता था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी की तुलना उसी से की थी लेकिन सरकार ने विपक्ष की एक न सुनी और पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया। वही समय-समय पर जीएसटी की बैठक में इस टैक्स प्रणाली पर सुधार अवश्य किया जाता रहा। लेकिन सबसे बड़े सुधार की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से देश को संबोधित करते हुए कहा कि, देशवासियों को दिवाली पूर्व जीएसटी दरों में कमी करके तोहफा दिया जाएगा। उसी के अनुरूप जीएसटी की बैठक में देश की वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने घोषणा की कि, अब देश में दो स्लैब की संरचना अपनाई जाएगी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। वही विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत हाई टैक्स लागु किया जाएगा।

सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि, आम आदमी के सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक उपयोग में आने वाली लगभग सभी वस्तुए सस्ती हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि, पहले जीएसटी की चार श्रेणियां थी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत जिसे सरल करके 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। 5 प्रतिशत के दायरे में आने वाली अधिकतर वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत व 12 और 18 प्रतिशत वाली अधिकतर वस्तुओं को 5 प्रतिशत तक के दायरे में लाया गया है। सरकार का कहना है कि, इससे आम नागरिको की क्रयशक्ति बढ़ेगी और सरकार को भी टैक्स में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आगामी त्यौहारों को देखते हुए सरकार द्वारा आम आदमी को दिए जाने वाले तोहफे के रूप में सरकार इसे प्रचारित कर रही है।

वही आम नागरिक इससे हटकर कुछ बातों को लेकर चिंतित है और सरकार को चाहिए कि, आम आदमी की इन चिंताओं को दूर करे। सबसे बड़ा सवाल यह है क्या वास्तविक रूप से आम नागरिकों को इस जीएसटी कटौती दर का लाभ मिल पाएगा...? क्योंकि आम आदमी का यह सोचना है कि, किसी भी सामान की कंपनी द्वारा कीमत तय करने के बाद उसमें कटौती करना मुश्किल होता है और अगर सरकार ने टैक्स में छूट दी है तो कंपनियां अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाकर वस्तु की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसी प्रकार बीमा पालिसियो पर भी टैक्स की कमी के बराबर कंपनियां अपनी प्रीमियम राशि बढ़ा देगी। यही नहीं खाने-पीने की अन्य वस्तुओ के दाम भी निजी कंपनियां अपनी मनमानी से बढ़ा सकती है। क्योंकि, आम नागरिकों का कहना है कि, पुराने अनुभवो के आधार पर हम यह कहते हैं कि, जीएसटी सुधार का लाभ आम नागरिकों को न मिलते हुए बड़ी-बड़ी कंपनियों के खाते में जा सकता है।

वहीं आम नागरिकों का कहना है कि, अगर सरकार वास्तव में इन सुधारो का लाभ आम जनता को देना चाहती है तो उसे सभी कंपनियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और आम नागरिक को पुरानी कीमत और नई कीमत के बारे में स्पष्ट जानकारी देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कंपनी को अपने किसी भी उत्पादन की कीमत फिलहाल नहीं बढाने के निर्देश दिया जाना चाहिए। ताकि जीएसटी की कटौती का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। वहीं अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों को भी निर्देशित किया जाना चाहिए कि वो इस कटौती का लाभ अपने पॉलिसी धारक को वास्तविक रूप से दे।

पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए

निश्चिय ही जीएसटी दरो में की गई कमी से आम उपभोक्ता को वस्तुएं सस्ती मिलेगी बशर्ते सरकार इसे पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ लागू करवाए। वही आम उपभोक्ताओ का कहना है कि, ईंधन (पेट्रोल और डीजल) को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए जिससे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाए। जिससे दाम कम होने पर परिवहन लागत में कमी आएगी और इसका सीधा असर रोजमर्रा के सामान पर पड़ेगा और वे सस्ते हो पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक यदि पेट्रोल-डीजल का 40 प्रतिशत स्लेब में रखा जाता है तब भी वर्तमान कीमत से इन पदार्थों की किमत कम हो जाएगी। वर्तमान में पेट्रोल और डीजल पर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दरों पर वेट टेक्स लगाया जा रहा है। हालांकि इससे राजस्व में कमी आएगी और राज्यो को नुकसान हो सकता है। जिसके लिए राज्य सरकारे राजी नहीं है लेकिन आम जनता के हितों के लिए इस प्रकार का कदम सरकार को उठाना चाहिए क्योंकि शासन व्यवस्था का मूल मंत्र सर्वजन का हित है।

ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को सीधा संदेश

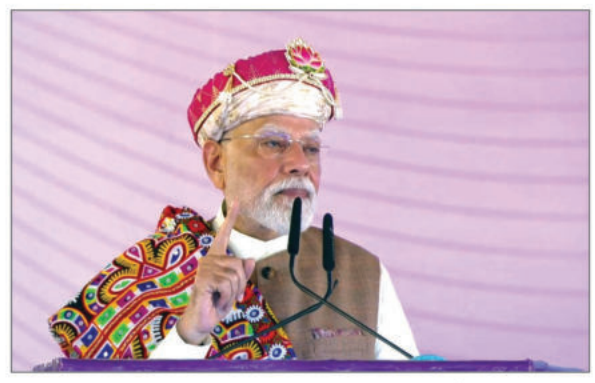

माही की गूंज, धार।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, यह नया भारत है, जो आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है और किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि, हमारी बेटियों के सिंदूर को मिटाने वाले आतंकियों पर निर्णायक प्रहार किया गया।

अपने 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया और स्वस्थ नारी,सशक्त परिवार अभियान, राष्ट्रीय पोषण माह, आदि कर्मयोगी अभियान तथा सुमन सखी संवाद सहायक की शुरुआत की।

पीएम ने कहा कि, विकसित भारत के चार स्तंभ हैं महिलाएं, युवा, गरीब और किसान। यदि मां स्वस्थ रहती है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है। इसी सोच से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को मजबूत किया जाएगा तथा कैंसर, एनीमिया, मधुमेह जैसी बीमारियों की समय पर पहचान होगी।

मोदी ने बताया कि, अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 4.5 करोड़ से अधिक माताओं को लाभ मिला है और 19 हजार करोड़ रुपए उनके खातों में जमा किए गए हैं। देशभर में 75,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मोदी ने कहा कि यह अभियान आदिवासी समाज और पूरे देश की माता-बहनों को सशक्त बनाने का सेतु बनेगा।

22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़

नई दिल्ली, एजेंसी

अर्धकुंवारी में भूस्खलन की वजह से व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसके बाद माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया था। पिछले तीन सप्ताह से भी ज्यादा समय से यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा था। पुनर्निर्माण में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रयास रंग लाया और नवरात्रि से ठीक पहले माता वैष्णो देवी मार्ग को बहाल कर दिया गया है।

22 दिन के विराम के बाद शुरू हुई यात्रा को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखा जा रहा है। आधार शिविर कटरा स्थित पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ÷चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है÷ कृएक बार फिर यही स्वर गूंजने लगा है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के फैसले से श्रद्धालुओं में उत्साह है।

कटरा स्थित आधार शिविर पर पंजीकरण काउंटर पर भक्तों की भीड़ देखी गई। यात्रा फिर से शुरू करने का यह निर्णय तीर्थयात्रियों के एक समूह द्वारा यात्रा बहाल करने की मांग के समर्थन में आधार शिविर कटरा में हुए विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद आया। इससे पहले, प्रबंधन बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण इसे टालना पड़ा। इसके चलते श्रद्धालुओं ने विरोध किया और सुरक्षा घेरे को तोड़कर यात्रा करने की कोशिश भी की थी।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा अनुकूल मौसम की स्थिति में बुधवार को फिर से शुरू हो गई है। बोर्ड ने नवरात्रि से पहले देश और विदेश के लाखों-करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी दी है।

बता दें कि यह यात्रा 26 अगस्त को स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि मंदिर मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा घायल हुए थे।

बोर्ड ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा थाकृजय माता दी3 वैष्णो देवी यात्रा अनुकूल मौसम की स्थिति में 17 सितंबर 2025

(बुधवार) से शुरू होगी। भक्तों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सूचना माध्यमों से जानकारी प्राप्त करें।

पिछले दिनों जम्मू संभाग में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। अर्धकुंवारी के पास भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें लगभग तीन दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इसके चलते यात्रा मार्ग बंद करना पड़ा। लगातार मरम्मत के बाद 22 दिनों के बाद आखिरकार 17 सितंबर 2025 को यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया।

बैंक कर्मियों को बांधकर 58 किलो सोना और 8 करोड़ नगदी की लूट

बेंगलुरु, (ईएमएस)।

कर्नाटक के विजयपुरा ज़िले के चादचान कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मंगलवार शाम हुई बड़ी लूट ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। पाँच लुटेरों ने फौजी जैसी वर्दी पहनकर बैंक में धावा बोला और कर्मचारियों को बंधक बनाकर 58 किलो सोना तथा करीब 8 करोड़ रुपये नकद लूट लिए।

लुटेरे घटना के बाद बैंक से फरार हो गए, लेकिन उनकी इस्तेमाल की गई कार महाराष्ट्र के पंढरपुर से बरामद हुई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त रूप से पंढरपुर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वारदात मंगलवार शाम लगभग पाँच बजे की है। लुटेरे देशी तमंचों और अन्य हथियारों से लैस थे। बैंक में घुसते ही उन्होंने प्रबंधक, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकाया और अलार्म बजाने से रोक दिया। इसके बाद सभी को रस्सियों से बांधकर तिजोरी तोड़ी और सोना व नकदी लेकर फरार हो गए।

लूट के बाद लुटेरे सफेद रंग की कार से भागे। बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। चादचान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बुधवार सुबह महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के पंढरपुर में एक सुनसान जगह पर वही कार बरामद हुई। गाड़ी खाली थी, लेकिन उसमें से लूट के सबूत जैसे रस्सियाँ और नकाब मिले। कर्नाटक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन का नंबर मिल चुका है और यह वही कार है जिसमें लुटेरे भागे थे। आशंका है कि अपराधी कार छोड़कर दूसरे साधन से फरार हो गए होंगे।

दोनों राज्यों की पुलिस की टीमों ने पंढरपुर, सोलापुर और सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी है। डॉग स्क्वॉड और वैज्ञानिक साक्ष्य टीम को भी लगाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह लूट कर्नाटक में हाल ही में हुई बैंक डकैतियों की कड़ी मानी जा रही है। कुछ महीने पहले दावणगेरे में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से 17 किलो सोना चोरी का मामला सामने आया था, जो प्रसिद्ध धारावाहिक मनी हाइस्ट से प्रेरित था।

किसकी कठपुतली...? लंका, बांग्लादेश और फिर नेपाल में अचानक तख्ता पलट

नई दिल्ली, एजेंसी।

लंका, बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह से अचानक युवाओं के आंदोलन की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, यह कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एशिया के देश किसी ताकत के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। इन देशों में जो भी सरकारें थीं, वे पश्चिम विरोधी मानी जाती थीं। वहीं इन सभी सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था।

लंका में सत्ता परिवर्तन होने में तीन महीने का वक्त लगा तो बांग्लादेश में 15 दिन का। वहीं नेपाल में जनरेशन-ज़ेड ने मात्र दो दिन में ही सरकार उखाड़कर फेंक दी। सोशल मीडिया से शुरू हुआ आंदोलन जब सड़कों पर आया तो किसी भी देश की सरकार में इतनी ताकत नहीं थी कि वह इसे संभाल पाती।

अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया मंच हैं, वे ज्यादातर अमेरिकी हैं। टिकटॉक चीन का है। वहीं डिस्कॉर्ड, वाइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मातृ कंपनियां अमेरिकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह से सत्ता परिवर्तन करवाने वाली ताकत अमेरिका में है या फिर रूस में, या फिर चीन में?

काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को पश्चिमी मीडिया ने नेता घोषित कर दिया था। गौर करने वाली बात है कि नेपाल, पश्चिम बंगाल और लंका की सरकारों का झुकाव चीन की तरफ था। राजपक्षे ने हंबनटोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया तो वहीं शेख हसीना चटगांव और मोंगला समुद्र-बंदरगाह चीन

को देने की तैयारी कर रही थी। नेपाल की ओली सरकार अपनी जमीन के जरिए चीन के बंदरगाहों को आने-जाने का रास्ता देने वाली थी।

गौर करने वाली बात है कि आंदोलन से 6 दिन पहले ही ओली चीन पहुंचे थे और विजय दिवस परेड में शामिल हुए थे। उस समय चीन को भी अंदाजा नहीं था कि नेपाल में क्या होने वाला है। यहां तक कि भारत की एजेंसियों को भी भनक नहीं लगी कि पड़ोसी देशों में क्या उथल-पुथल होने जा रही है।

इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक और गणितीय सूत्रों वाले इस युग में किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन अचानक हो सकता है। कट्टरपंथ, राजनीतिक ध्रुवीकरण और उकसावे को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है। जिन संस्थानों को बनने में सालों लग गए, उन्हें मिनटों में तबाह किया जा सकता है।

एक बात और नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि जिन देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां की सरकारें प्रशासन के मामले में काफी ढीली थीं। युवाओं में बेरोजगारी चरम पर थी। इन तीनों ही देशों में भ्रष्टाचार चरम पर था। पाकिस्तान और म्यांमार में अगर सेना हावी न हो गई होती तो ऐसा ही कुछ वहां भी होने वाला था।

भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और जनता के साथ एक रिश्ता कायम किया है और लगातार जुड़े रहते हैं। ऐसे में सरकार को भी इस बात का अंदाजा रहता है कि युवा क्या चाहता है। आज के युग में वास्तविकता से ज्यादा कोई भी धारणा असर करती है।

राजनीतिक बहस का गिरता स्तर, भारत ही नहीं वैश्विक चुनौती बन गई

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत समेत दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक बहस का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जहां कभी विचारधारा, नीतियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती थी, वहीं आज व्यक्तिगत हमले, अपशब्दों का प्रयोग और आपसी कटाक्ष सामान्य बात हो गई है।

यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और एशिया के अन्य देशों में भी राजनीतिक संवाद की मर्यादा टूटती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक माध्यम ने इस गिरावट को और तेज कर दिया है। पहले नेताओं की बहस और वक्तव्य संसद या सभाओं तक सीमित रहते थे, लेकिन आज हर बयान तुरंत फैल जाता है।

इसके चलते राजनेता लोकप्रियता पाने के लिए अक्सर भड़काऊ या विवादित बयान देने से भी नहीं चूकते। जनता का ध्यान गंभीर मुद्दों से हटाकर भावनात्मक विषयों पर केंद्रित करना अब इन नेताओं की एक रणनीति बन गया है। भारत में भी संसदीय कार्यवाही के दौरान शालीनता और मर्यादा की परंपरा क्षीण होती नजर आ रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच स्वस्थ बहस की जगह आरोप-प्रत्यारोप और व्यक्तिगत कटाक्ष देखने को मिलते हैं।

यह स्थिति लोकतंत्र की उस बुनियादी भावना के विपरीत है जिसमें मतभेदों को संवाद और तर्क से सुलझाने की अपेक्षा की जाती है। वहीं अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान बहस में अपशब्दों का इस्तेमाल, प्रतिद्वंद्वी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी और नीतिगत सवालों से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। इसी तरह ब्रिटेन में ब्रेग्ज़िट के समय हुई बहसों ने भी यह दिखाया कि राजनीतिक संवाद किस तरह समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा सकता

है। फ्रांस और जर्मनी में भी चुनावी बहसें अक्सर कटाक्षों और भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रह जाती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह रुझान लोकतंत्रों के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि इससे जनता का भरोसा घटता है और संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर होती है। नैतिकता और मर्यादा केवल नेताओं के व्यक्तिगत गुण नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए जरूरी आधार है।

यदि राजनीतिक बहस का स्तर इसी तरह गिरता रहा तो आम नागरिक नीतिगत मुद्दों से दूर होते जाएंगे और लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने की जंग तक सिमटकर रह जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल और उनके नेता इस गिरावट को रोकने के लिए आत्ममंथन करेंगे? समाधान इसमें है कि बहस को मुद्दों पर केंद्रित किया जाए, व्यक्तिगत कटाक्षों से बचा जाए और जनता को सार्थक विकल्प दिए जाएं। तभी राजनीतिक संवाद का स्तर सुधर सकेगा और लोकतंत्र की असली ताकत।

व्यवस्था पर कटाक्ष

2 अक्टूबर को गांधी जयंती (ड्राय डे) के साथ दशहरा भी इसलिए बहेगी अवैध शराब व झूमेंगे शराब प्रेमी

दशहरे के लिए अवैध शराब विक्रेताओ के लिए हो विशेष परमिट की व्यवस्था...!

माही की गूंज, झाबुआ।

2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और संयोग से इस बार दशहरा भी दो अक्टूबर को ही आ रहा है। दोनो मामलो में कोई विशेष जुड़ाव तो नही है लेकिन दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर ड्राई डे (शुष्क दिवस) होता है जिसके चलते देश भर की सरकारी शराब की दुकाने बंद होती है। वही शराब व मांस का सेवन करने वालो के लिए दशहरे का त्यौहार मान-मन्नत और खाने-पीने के दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन शराब की खपत भी रोज के मुकाबले बेहत बढ़ जाती है। जिससे शराब ठेकेदार इस बार दशहरा पर्व पर ड्राई डे होने के कारण शासकिय ठेके की दुकान पर शराब नही बैच पाएगा। लेकिन जिले की कुल 33 शराब की दुकानों की एवज में सेकडो अवैध शराब की दुकानें प्रत्येक गांव व गली-मोहल्लों में खुली है, जहा आम जनता को तो ये अवेध दुकानें खुली आखों से दिखती है। तथा लोग खुले आम सुरा पान लिए इन अवैध दुकानों पर आते-जाते है। यहां तक कि बैठ कर शराब पीते भी नजर आते है लेकिन अवैध शराब पर कार्रवाई के लिए बने आबकारी विभाग और पुलिस को खुली आखों से ये अवैध शराब की बिक्री होते नही दिखती। ये माही की गूंज की खबरों का ही असर है कि, जिले में आयोजित होने वाले बड़े कुछ धार्मिक त्योहारों पर जिन गावो में धूमधाम से मनाए जाते है वहा एक निश्चित समय के लिए इन अवैध शराब के धंधे करने वालो पर रोक आबकारी और पुलिस द्वारा लगाई जाती है। इस बार गांधी जयंती पर कहने के लिए भले शराब की वैध दुकानें बंद रहेगी लेकिन अवैध शराब की दुकानें सरकार, शासन-प्रशासन और महात्मा गांधी जी का मुंह चिढ़ाते खुली नजर आएगी।

सोशल मीडिया पर भी छिडी जंग इस 2 अक्टुम्बर को गांधी जयंती मनाएगें या दशहरा...?

दशहरे के लिए परमिट जारी करे आबकारी विभाग...?

ये तय हैं की गांधी जयंती या और कोई सरकारी रोक न तो वैध शराब ठेकेदार का अवैध शराब सप्लाई रुकेगा और न ही अवेध शराब की बिक्री। खुले रूप से होने वाली अवैध शराब बिक्री से होने वाली बदनामी और दशहरे जैसे पर्व पर शराब ठेकेदार को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आबकारी विभाग को दशहरे से पहले शराब ठेकेदार और अवैध शराब विक्रताओ को दो दिन पहले तक के परमिट जारी कर दे। ताकि दशहरा पर्व के लिए क्षेत्र के शराब ठेकेदार होल सेल में शराब अवैध शराब विक्रेताओं को स्टॉक फूल कर दे और इन दो दिन के परमिट में अवेध शराब विक्रेताओं जो की वैसे भी बेरोकटोक बिक्री जारी रखेंगे उनको दिया जाए ताकि बेखौफ होकर दशहरे पर शराब प्रेमियों को किसी तरह की समस्या नही आए। आबकारी विभाग ये भी निश्चित करें की किसी भी परिस्थिति में अवैध शराब विक्रेताओं के पास शराब खत्म होने की दशा में क्षेत्र के शराब ठेकेदार को होल सेल (नियम विरुद्ध) बिना शटर खोले देने का परमिट देना चाहिए।

महात्मा गांधी के आदर्शों को भूलने के लिए याद रखा जाएगा ये दशहरा...

हमे तो याद भी नही की दशहरा और गांधी जयंती दोनो एक साथ एक दिन कब आए होगें लेकिन इस बार ये संजोग बना है तो ये भी तय है ये दशहरा महात्मा गांधी के आदर्शों को भूलने के लिए याद रखा जाएगा। जहा एक राज्य गांधी जी के नाम से शुष्क प्रदेश (गुजरात) को घोषित किया गया है और देश भर में गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रखी जाती है। पूरे मध्यप्रदेश तो ठीक लेकिन झाबुआ जिले में दो अक्टूबर को शराब की नदिया वैध की अवैध फ्रेंचाईसी पर दशहरे के दो दिन पुर्व से अवैध शराब का स्टाक 1 अक्टुम्बर रात जब आबकारी द्वारा शासकीय ठेके की दुकानो को सिल करने तक किया जाएगा। तथा उक्त अवैध शराब दशहरे 2 अक्टुम्बर गांधी जंयती पर जमकर बहेगी और आबकारी विभाग के हिस्से में नोटो के बंडल आयेगें जिससे गांधी जी के आदर्शों और सरकारी नियमो को खुलेआम कुचला जायेगा। ऐसे में दशहरे हेतु सरकार द्वारा आबकारी के माध्यम से अवैध शराब विक्रेताओ को शराब ले जाने व बेचने हेतु परमिट देना जायज रहेगा...!

एसडीएम के खिलाफ पत्रकारों का सामूहिक निंदा प्रस्ताव

माही की गूंज, पेटलावद।

नगर के पत्रकारों ने एक आपात सामूहिक बैठक रविवार को रूपगढ़ रोड स्थित पूर्व मुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित कर मुख्यमंत्री की सभा को लेकर पेटलावद एसडीएम तनु श्री मीणा द्वारा स्थानीय पत्रकारों के साथ किए गए पक्षपात पूर्ण व्यवहार की कड़ी निन्दा कर एसडीएम मीना के विरुद्ध बैठक में सामूहिक निंदा प्रस्ताव पास किया गया। एसडीएम के व्यवहार को लेकर पत्रकारों में रोष व्याप्त है। नगर के पत्रकारों की उपस्थिति में उक्त निंदा प्रस्ताव पास कर भविष्य में इस प्रकार के प्रशासन के निर्णय का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया। मामला 12 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा का है जहां पत्रकार दीर्घा में बैठने को लेकर पेटलावद एसडीएम तनु श्री मीणा द्वारा स्थानीय पत्रकारों को पास जारी करना थे लेकिन एसडीएम द्वारा पत्रकारों को आयोजन से दूर रखने के घृणित प्रयास किए और कई स्थानीय पत्रकारों को सभा के लिए पास जारी नहीं किए। पास नही मिलने को लेकर पीआरओ झाबुआ ने पत्रकारों को एसडीएम के हस्ताक्षर बाकी होने का हवाला देकर गुमराह किया और बाद में कार्यक्रम के ठीक पहले पता चला की जिन पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज थे उनको पास जारी नही किया गया। आयोजन स्थल पर बिना एसडीएम द्वारा जारी पास के पहुंचे पत्रकारों को बाहर करने का कथित प्रयास एसडीएम द्वारा किया गया जिसका विरोध करते हुए समस्त पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात कही। जिसके बाद पीआरओ और कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। एसडीएम के द्वारा पत्रकारों के साथ जान बूझकर इस प्रकार की घटिया हरकत की गई जबकि मंच पर मौजूद कई जनप्रतिनिधियों ,ड्यूटी पर तैनात कई कर्मचारियों और मुख्यमंत्री से मिलने और स्वागत करने वाली सूची में कई लोगो के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज है। लेकिन एसडीएम तनु श्री मीणा ने केवल पत्रकारों को निशाना बना कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। जिसकी पत्रकारों ने कड़ी निन्दा

कर एसडीएम के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया हैं। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण शर्मा, हरिशंकर पवार, मनोज पुरोहित ,वीरेंद्र भट्ट सहित जीतेश विश्वकर्मा , निर्मल व्यास,मुकेश सिसोदिया, सत्यनारायण गौड़, राकेश गेहलोत, प्रकाश पडियार, लोकेंद्र सिंह परिहार, गोपाल राठौर, तन्मय चतुर्वेदी, चंदू राठौर, धर्मेंद्र सोनी, राकेश डूंगरवाल ,ओपी मालवीय, तरुण चौधरी ,दीपक निमजा, शब्बीर मंसूरी, अर्जुन ठाकुर ,उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों ने अन्य विषयो पर चर्चा कर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए।

गलत व्यवहार को लेकर लगातार विवादो में आईएएस एसडीएम मीणा

लगभग एक वर्ष से पेटलावद अनुभाग में पदस्थ आईएएस एसडीएम मीणा यहा पदस्थ होने के बाद से अपने व्यवहार को लेकर लगातार सवालो के घेरे में है। पुलिस विभाग के थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर तक उनके गलत व्यवहार का शिकार हो चुके है। वही विकास खंड के समस्त पटवारी भी मैडम के एक तरफा व्यवहार को लेकर धरना दे चुके है । क्या पत्रकार, क्या नेता और क्या जनप्रतिनिधि मैडम द्वारा अशोभनीय व्यवहार की बाते सामने आती रही है। यहां तक की क्षेत्र की विधायक और केबिनेट मंत्री के क्षेत्र के दौरे पर भी मैडम किसी न किसी कारण बता कर दूरी बना लेती है और कई बार बीच कार्यक्रम से निकल जाती है। केबिनेट मंत्री के पास कई शिकायते एसडीएम की जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई या सख्त हिदायत मंत्री जी की ओर से भी देखने को नही मिल रही। सूत्रों के अनुसार मंत्रीजी के चलते आयोजनों में एक-दो बार मैडम को फटकार लगा कर व्यवहार सुधारने की हिदायत दे चुकी है लेकिन कोई सुधार नहीं देखा गया।

ज्ञापन लेने तक ऑफिस से बाहर तक नही आती एसडीएम, किसान आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है एसडीएम

तनु श्री मीणा एसडीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली चुनौती किसानो से मिली थी जब किसान लाड़की नदी में उतर कर अपनी मांगे सरकार से रख कर आंदोलन कर रहे थे। यहां समझदारी दिखा कर किसानो को आश्वत करने का समय था लेकिन मैडम ने मौके पर जाना भी मुनासिब नही समझा और आंदोलन को बड़ा बना दिया। कई मांगो को लेकर ग्रामीण ,कर्मचारी ,संगठन और राजनेतिक दल अपने ज्ञापन लेकर कार्यालय पहुंचते है। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते सभी की सुन कर उनकी बातो को निश्चित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस स्थिति में मैडम अपने केबिन से निकल कर किसी की बात तक नही सुनती और ज्ञापन लेकर आए लोगो में से तीन चार लोगो को केबिन में बुला कर ज्ञापन स्वीकार करने की बात की जाती है। कई बार नाराज लोग बाहर कर्मचारियों को ही ज्ञापन थमा कर चले जाते है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले भी किसानो की फसल बीमा की मांग के ज्ञापन नही लेना क्षेत्र में बड़े किसान आंदोलन को पैदा कर दिया और मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले किसानो ने रायपुरिया राजगढ़ मार्ग बंद कर दिया था। कुल मिला कर एसडीएम मीणा अपने पद के साथ स्वयं ही न्याय करती नही दिख रही है। जिससे आम जनता,कर्मचारियों, जनप्रतिनिधीयों को परेशान होना पड़ रहा है जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार और क्षेत्र के सत्ताधारी नेताओ को भुगतना पड़ रहा है।

आरडीएसएस के तहत हुए कार्य में किया गया भ्रष्टाचार

निर्माण करने वाली एजेंसी अधूरा कार्य छोड़कर हुई भूमिगत

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोलंकी

केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट (आरडीएसएस) केंद्र की पुनरूत्थान योजना के तहत गांवों जिसमे मजरे व छोटे-छोटे गांव जो दूरस्थ क्षेत्र में है। जहाँ विद्युत नहीं पहुंची वहां 24 घंटे विद्युत लाइट देने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण अंचलों में आरडीएसएस के तहत कार्य किया जा रहा है। जिसमें कई ग्रामीण अंचलों में बाहर की निर्माण एजेंसियां कार्य कर रही है। जिम्मेदार अधिकारियो की लापरवाही के कारण व सतत मॉनेट्रिंग व निगरानी नहीं होने के कारण निर्माण एजेंसी अपनी मनमानी पर कार्य करने पर उतारू है। जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में कई जगह कार्य आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी व उनके जिम्मेदार सिविल इंजीनियर भूमिगत हो गए हैं।

कुछ ऐसा ही मामला खवासा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत नवीन ग्रीड सेमलिया (नारेला) में नया निर्माण किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इसके निर्माण कार्य का काम स्पान कंपनी नोएडा नई दिल्ली है। जिसमें उन्होंने नई ग्रिड़ सुचारू रूप से कार्य करने के साथ ही वहां विद्युत के कई बड़े-बड़े डीपी आदि लगा दिए गए हैं। तो ग्रीड को सुचारू रूप से अधिकारियों के सानिध्य में वोल्टेज की समस्या को देखते हुए शुरू कर दिया और साल भर हो गए। लेकिन ग्रीड जब से शुरू किया गया तब से कार्य भी अधूरा है। जिसके कारण वहां लाइन सप्लाई करने वाले ऑपरेटर को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि कई जगह बाउंड्री वॉल बाकी है। तो वहां उनको टॉयलेट के लिए आने-जाने के लिए लेट बाथरूम आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। जबकि वहां ऑपरेटर रात दिन ड्यूटी पर लगे हुए है उनका कहना है, कि ठेकेदार ने भवन व विद्युत लाइन चालू होने के बाद अभी तक यहां फिर कार्य करने ही नहीं आया जिसकी वजह से हमें परेशानियां हो रही है। आखिर किस वजह से वहां आज भी कार्य अधूरा पड़ा है? यह जाँच का विषय है। बताते हैं कि, सेमलिया ग्रीड से लेकर मेने लाइन तक 9 किलोमीटर तक इसी लाइन पर नए खंबे के साथ तार बिछाने का काम स्पान कंपनी को नए सिरे से करना था। लेकिन कंपनी के कर्मचारी व विद्युत विभाग के अधिकारियो की मिली भगत से भ्रष्टाचार किया गया। जिसके कारण वहां पुराने खम्बे पर ही 11 केवी लाइन डाल दी गई। तथा नियमों के विपरीत आज भी इस्टीमेट के अनुसार कार्य नहीं हुआ। जब भी अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि, नई लाइन बिछा दी जाएगी और ठेकेदार ने जितना काम किया है, उतनी ही बिलिंग का भुकतान किया जाएगा यह कहकर बात को ठन्डे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन साल भर से अधिक समय हो गया लेकिन ना तो वहां नई लाइन डाली ना भवन के अंदर जो काम बाकी है उसको अभी तक पुरा नहीं किया गया है। पुरानी लाइन पर ही पूरा सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है।

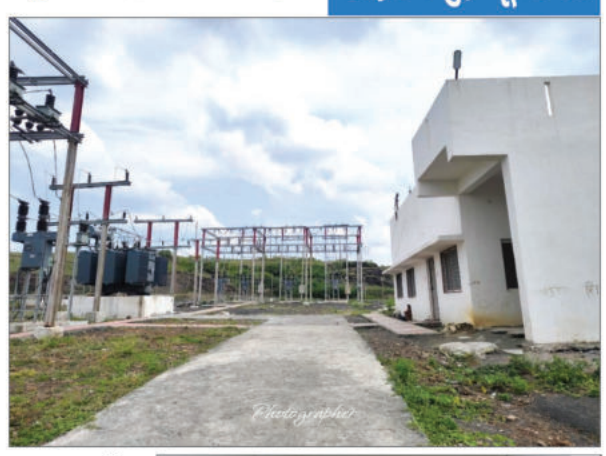

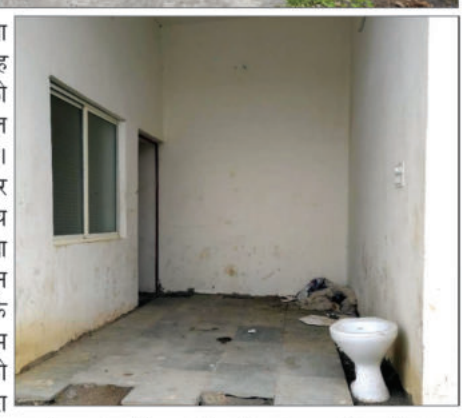

सेमलिया ग्रीड के लाइनमैन रतन चंद्रावत ने बताया कि, साल भर हो गया है स्पान कंपनी की तरफ से सिविल इंजीनियर रामजी साहू है, वह अभी तक यहां आए नहीं है। आखिर किस वजह से कार्य अधूरा पड़ा है यह तो वो ही बता पाएंगे, बाकी यहां हमें परेशानी होती है यह बात सही है। क्योंकि यहां शौचालय का काम अभी बाकी है और बाउंड्री वॉल भी बाकि है। ज्यादा जानकारी आपको हमारे वरिष्ठ अधिकारी ही दे पाएंगें।

भारतीय ज्ञान के द्वारा समाज में फैले झूठे विमर्श को करना होगा समाप्त

माही की गूंज, झाबुआ।

विश्वभर में शिक्षा पर इसीलिए जोर दिया जाता है, ताकि समाज में शिक्षा से उन्नति हो, उन्नति से विकास होकर मानव जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए गए किंतु बहुत से परिश्रम विफल रहे और उस स्थिति के अनुसार वर्तमान में भी यह स्तर है कि, भारत वर्ष में सभी नागरिक शिक्षित नहीं है साथ ही 10 प्रतिशत से अधिक निरक्षर है। स्वतंत्रता के बाद किए गए प्रयासो की सार्थकता पर संदेह है जो कि सुस्पष्ट दिखाई देता है।

भारतीय ज्ञान को विदेशी आक्रांताओ ने समाप्त करने की कोशिश की, जब वे पूर्णरुप से इसमें भी सफल नहीं हुए तब उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय ज्ञान के सम्बंध में झुठा नेरेटीव फैलाना शुरु कर दिया। जिसके कारण बच्चों को जो भारतीय शिक्षा पहले घरों में ही प्राप्त हो जाती थी वह उनको मिलना धीरे-धीरे बंद हो गई, और प्रचलन में कुछ और ही समावेश होता गया। वर्तमान में बच्चा जब स्कूल जाता है तब वह शैक्षणिक पाठ्यक्रम में उलझकर रह जाता है, इस पाठ्यक्रम से शिक्षित हो जाता है, और रोजगार के लिए अपनी डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में जुट जाता है। नौकरी मिलने पर कार्यालय के नए तौर तरिके सीखते हुए काम करते-करते आधा जीवन निकाल देता है। इस पूरे चक्र में वह बुद्धी से प्रबल नहीं हो पाता और न ही कभी ज्ञान के मार्ग पर चल भी पाता है।

भारत को वैचारिकरुप से प्रभावित करने वाले अज्ञात शत्रुओं ने नैरेटीव बनाकर भारतीयों को ही भारतीय ज्ञान से दूर कर दिया जिसके कारण वे दूसरों के अनुरुप अपनी जीवन शैली को बनाने लगे और झुठे विमर्श के कारण वे अपने मुल्यों को तर्क और विज्ञान के अनुरुप समझ भी नहीं पाए। इसके बहुत से गलत परिणाम सामने आए है जिसमें मुख्य रुप से है, कि, अशिक्षत अन्य प्रलोभन में आ कर मतांतरित होते रहे। एक और मुख्य परिणाम है जो सामने दिखाई देता है वह यह है कि, वर्तमान स्थिति में भारतीय घर रोगों का भंडार बनता जा रहा है। हर घर में कुछ ऐसे रोग है जिनके लिए वृद्ध अग्रेजी एलोपैथी दवाई का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी बच्चा बिमार तो कभी बच्चे की मां बिमार रहती है, और भी बहुत से परिणाम ऐसे है जो झुठे नेरेटीव के कारण भारतीयों के लिए संकटमयी, और गलत साबित हो रहे हैं।

झुठे विमर्श को त्यागना होगा और इसके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः विकसित करना होगा, जो कि बहुत कठीन कार्य नहीं है। जानकारी के अनुसार केन्द्र और प्रदेश सरकार विद्यालय या महाविद्यालय से जुड़ी शिक्षा में पुरातन भारतीय ज्ञान को सम्मिलित करने जा रही है। पाठ्यक्रम में वैदिक गणित, सृश्रुत संहिता की शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के साथ महाभारत काल में जिस गुणवत्ता से खेती की जाती है उसको भी रखा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अलग से एक डिवीजन बनाया है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में तेजी से जुटा हुआ है। साथ ही इसके स्कूल व उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे खेल व गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने की पहल की गई है जो भारत के ज्ञान पर केन्द्रीत है।

समाज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सहयोग कर झुठे विमर्श को समाप्त करने में सार्थक हो कर युवाओ को प्रबुद्ध बनाने में सफलता ला सकता है। समाजिक संगठनों को भारतीय ज्ञान परंपरा की कार्यशाला आयोजित करवानी होगी जिसमें महाभारत और रामायण के साथ श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान तार्किक रुप से वर्तमान परिवेश को जोड़ते हुए बताया जा सकता है, जिससे युवाओ की समझ बढ़ती जाएगी और वे बुद्धी के विकास की श्रेणी में आकर भारतीय ज्ञान, विज्ञान सीखकर प्रबुद्ध कहलाएगे।

शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार भारतीय ज्ञान, परंपरा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में महाभारत, रामायण, और गीता का अलग से एक विषय बना ले जो कि, पांचवी कक्षा से बारहवी कक्षा तक अनिवार्य कर दे तो विद्यार्थियों की बारहवी कक्षा तक बुद्धी, विवेक का स्तर उत्तम हो जाएगा। जिससे वे शारीरिक और व्यवहारिक ज्ञान में परिपूर्ण होकर अपने कौशल को विकसित करते हुए ज्ञान, विज्ञान, या यांत्रिकी विषय को चुनकर अपने भावी जीवन को उच्चतम बनाकर सहज और सुखद जीवन शैली बना सकते हैं।

इस उच्चतम प्रयोग से भारतीय युवा भारत को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, प्रगति को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखने वाला प्रबुद्ध भारतीय युवा कहलाएगा। जिसमें आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की शक्ति का भरपूर बल होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्रम मंत्रालय के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत स्नातक युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए व्यवहारिक कौशल नहीं हैं। अर्थात डिग्री और नौकरी के बीच के सेतु में हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था पंगु है। यही कारण होता है कि, विधर्मी राजनीति में लोग, युवाओं को भड़का कर उनका उपयोग कर सत्य, धर्म, और सरकार के सही निर्णय के सामने विरोध के लिए भी उनको लामबंध कर देते हैं। अधिकतर विपक्ष इसी अज्ञानता का लाभ लेकर युवाओं को जागरुकता की झोली से दूर कर देते हैं और अपनी-अपनी रोटियां सेक लेते हैं।

रिंकेश बैरागी

हालांकि मध्यप्रदेश सरकार गांव-गांव में निरक्षर लोगों की परिक्षाएं आयोजित करवाकर उन्हें साक्षर की गिनती में सम्मिलित करना चाह रही है, परंतु प्रौढ़ शिक्षा के इस प्रयोग से बुजुर्ग सिर्फ अपना नाम, पता लिखना सीखेगें और कुछ-कुछ पढ़ सकेगें। इसके लिए प्रदेश सरकार करोड़ो का बजट खर्च कर प्रौढ़ शिक्षा की परिक्षाएं आयोजित करवा रही है। प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में करिब एक करोड़ 50 लाख के लगभग बुजुर्गो को प्रौढ़ शिक्षा की साक्षरता परिक्षा में सम्मिलित करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस लक्ष्य में जिला स्तर पर शिक्षा क्षेत्र के सभी विभागो को सहयोग करना है लेकिन कहीं-कहीं राज्य शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी कर्मचारी अपने सहयोग से पल्ला झाड़ रहे हैं। विशेष रुप से झाबुआ जिला ऐसा है जहां इसकी शिकायत सामने हमेशा से आती रही है।

बहरहाल जब सर्व गुण सम्पन्न ज्ञान की अविरल धारा भारतीय ज्ञान में प्रवाहीत होती है तो समाज की सभ्यता, और संस्कृति को पुनः स्थापित कर पाठ्यक्रम में महाभारत, रामायण, और गीता जैसे ग्रंथों का समावेश करना आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों की बुद्धी का विकास उच्च स्तर से होगा और यथा सम्भव झुठे विमर्श (नैरेटीव) का विनाश होगा।

तीन साल से चल रहा नल-जल योजना का कार्य आज तक नहीं हुआ पूरा

एक साल से लगी सेटिंग तक नहीं खोली ठेकेदार ने और एसडीएम साहब आलाप रहे अपना अलग ही राग

माही की गूंज, करवड/पेटलावद।

इस तरह से एक साल के लगभग से पानी की टंकी पर लगी हुई है सेंटिंग।

15 - ग्राम पंचायत रूनजी के ग्रामीण।

जगह-जगह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी महत्त्वकाशी नल जल योजना के माध्यम से घर-घर नल घर-घर जल पहुंचाने का दावा करते है। लेकिन वास्तविकता और धरातल पर योजना की स्थिति इतनी गंभीर है कि, योजना के नाम पर करोड़ों की लीपापोती हो रही है।

पेटलावद विकास खंड की कई ग्राम पंचायतों में नल जल मिशन योजना का कार्य चल रहा है लेकिन कई ग्राम पंचायतों में योजना केवल पानी की टंकी के रूप में दिखाई दे रही है आम जनता को इसका कोई सीधा लाभ नही होता दिखा रहा है। कई ग्राम पंचायतों में तो ये स्थिति है की योजना का कार्य वर्षो से रुका पड़ा है और जो कार्य हुआ है उसकी स्थिति भी जर्जर हो चुकी है कि, जब भी कार्य पूरा होगा पुराना कार्य इस लायक ही नहीं रहेगा की वो योजना को पूरा कर सके।

तीन वर्षो में कार्य पूरा नही हुआ रूनजी पंचायत में

पेटलावद विकास खंड में की ग्राम पंचायत रूनजी जहा पानी की गंभीर समस्या होने के चलते सरकार की ओर से ग्राम पंचायत को एक करोड़ के अधिक लागत से नल जल मिशन योजना का लाभ दिया। वर्ष 2022 में कार्य के टेंडर हुए और कार्य शुरू हुए तो ग्राम पंचायत के लोगो को उम्मीद थी की जल्द ही उनकी पानी समस्या से निजाद मिल जायेगी लेकिन तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तारीख तक कार्य पूरा नही हुआ न ही लोगो तक पीने का पानी पहुंच सका। दो से तीन बार ग्रामीण पेटलावद के अधिकारियो को आवेदन देकर ठेकेदार से कार्य पूर्ण करवाने की मांग कर चुके है लेकिन हर बार आश्वासन के साथ ठेकेदार कुछ दिन के लिए काम को आगे बढ़ाता और वापस अधूरा कार्य छोड़ कर चला जाता है।

एक वर्ष से लगी हुई है सेंटिंग खोलने तक नही आया ठेकेदार

कार्य में लापरवाही का आलम इस कदर है कि, ठेकेदार पानी की टंकी निर्माण के लिए लगाई गई सेंटीग तक नही खुली। ठेकेदार द्वारा टंकी की छत भरने के बाद न तो कोई तरी की न ही उसकी कोई देख-रेख।

ग्राम रूनजी के ग्रामीण दिनेश गामड़ पूर्व उप सरपंच और नेहरू गामड़ ने बताया कि, एक करोड़ सात लाख की लागत से आई योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की भेट चढ़ चुकी है और तीन साल बाद भी योजना पूरी नही हुई और न लोगो को इसका एक रुपए का लाभ मिला।

ग्रामीणों ने बताया कि, ग्राम के लोग आज भी गर्मी में पीने के पानी के लिए दो से तीन किलोमीटर दूर जाने पर मजबूर है । ग्राम पंचायत की सरपंच ने बताया कि, पूर्व में भी हम ग्रामीण जन एक साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को शिकायत दर्ज करवा चुके है जिसके बाद ठेकेदार कुछ समय के लिए काम करने आया और फिर गायब हो गया। जब से काम अधूरा पड़ा है न ही टंकी बनी न ही पाइप की लाइन सही से बिछाई गई।

पीएचई विभाग आलाप रहा अपना ही राग , कोई दूसरा ठेकेदार आने को तैयार नही

उक्त योजना का कार्य पीएचई विभाग के माध्यम से पूरा होना था लेकिन विभाग की लापरवाही देखिए तीन साल बाद भी इस प्रकार के घटिया निर्माण से ही पानी ग्रामीणों तक पहुंचाने की बात कर रहे है । विभाग एसडीओ बघेल इस संबध में बताते है की ठेकेदार यादव सिंह (आगर मालवा) क्षेत्र का और कार्य पूरा करने के लिए विभाग की ओर से दस से ज्यादा नोटिस जारी किए गए है । टंकी से पाइप जोड़ने का काम बाकी रहा है जो जल्द पूरा करवाया जायेगा और ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूरा नही करने की स्थिति में राशि काटने के भी नोटिस जारी किए गए। घटिया निर्माण जो की खुली आखों से कोई भी देख सकता है एसडीओ साहब को नजर नही आ रहा है। घटिया निर्माण पर साहब ठेकेदार और खुद के उपयंत्री को बचाते हुए कार्य में घटिया निर्माण नहीं होना बता रहे है। जबकि मौका स्थिति देख कर कोई भी कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नही होगा। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट करने की बात कहने पर साहब का कहना है कि, पूर्व में झकनावदा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट किया गया था उसका कार्य अभी तक पूरा नही हो सका है। क्योंकि अधूरे कार्य को पूरा करने को कोई ठेकेदार तैयार नही है। अगर यहां भी कार्य ठेकेदार छोड़ कर गया तो कार्य कोई भी नही करेगा। एसडीओ साहब तीन साल से रुक-रुक कर चल रहे कार्य को ही अच्छा बता कर कार्य पूरा करवा कर योजना शुरू करवाने की बात कर रहे है जो हथेली में हाथी दिखाने वाली बात लग रही है ।

सीएम हेल्प लाइन पर एक साथ 15 शिकायत

जल्द ही ग्राम पंचायत रूंनजी के ग्रामीण इस मामले को लेकर अधिकारियो के पास पहुंच कर शिकायत करने की मांग का कह रहे है। वही ग्रामीणों ने एक साथ लगभग 15 सीएम हेल्प लाइन इस मामले में दर्ज करवाई है। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री देश को बड़ी बड़ी योजना ग्रामीणों को समर्पित करने के दावे करते है और दूसरी ओर उनका ही सिस्टम उन दावो को जमीन स्तर पर फैल कर सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे है।

ट्यूबवेल में पर्याप्त मात्रा में पानी पर जल जीवन मिशन में बनी पानी की टंकी से नहीं मिल रहा पानी

माही की गूंज, खवासा।

केंद्र की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन जल मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों की सहूलियत के लिए पानी उपलब्ध करवाने की दिशा की ओर अग्रसर हो कर सरकार ने कई प्रोजेक्ट जल जीवन जल मिशन में बनाएं। जिससे कि, ग्रामीण अंचलों में लोगों को शुद्ध पानी मिल सके इसी उद्देश्य से कई जगह ट्यूबवेल के साथ पानी की टंकी, पाइपलाईन और लोगों के घरों तक नल स्टैंड लगाए ताकि ग्रामीणों को दूरस्थ अंचल से कहीं पानी लाने की जरूरत न पड़े। अगर थांदला जनपद क्षेत्र की ही बात करे तो यहा पर ही कई अनियमित्ताए देखी जा सकती है। जेसे बनाई गई पानी की टंकियां बन भी गई तो टंकीत क पानी नही पहुचा, कई जगह मोटर खराब हो चुकी है, तो कई जगह सरपंच व सचिव की हट धर्मिता के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला माही की गूंज को मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार सामने आया, जिसम माही नदी से सट्टे भेरूगढ़ पंचायत के अन्तर्गत बड़ी रामगढ़ मे 150 मकान के लिए केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर पीएचई विभाग थांदला सबडिवीजन के माध्यम से ठेकेदार के सानिध्य में एक टंकी का निर्माण किया। जिसमें टंकी बनाने के साथ ही दो ट्यूबवेल टंकी के पास लगाए गए तो आसपास घरों तक पाइपलाईन बिछा दी गई और नल कनेक्शन भी दे दिए, लेकिन नल स्टैंड ठेकेदार ने नहीं लगाए। पानी की टंकी बन कर तैयार हुए 3 साल के करिब हो गए है।

ग्रामीणों ने बताया कि, कुछ समय के लिए टंकी से पानी चालू भी हुआ। ठेकेदार ने नल स्टैंड तो नहीं लगाए सिर्फ नली लगाकर घरों के पास नल छोड़ दिए। थोड़े दिन पानी चला उसके बाद टंकी में कोई पानी चलने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। टंकी के समीप दो ट्यूबवेल लगाए गए हैं। जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी है। लेकिन बिजली की पूर्ति नहीं होने के कारण वह ट्यूबवेल भी बंद पड़े हुए हैं। जिससे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया लेकिन उन्होने सुना को अनसुना करके मामले में कोई आगे कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से टंकी आज शोपीस बनी हुई है। ग्रामीणो ने मांग की है कि जल्द से जल्द टंकी में सुचारू रूप से पानी सप्लाई किया जाए क्योंकि यहां पानी पर्याप्त मात्रा में है और गांव में पानी सप्लाई हो सके। भेरूगढ़ पंचायत के अंतर्गत बड़ी रामगढ़ में 150 मकान के करिब परिवार रहते है। अगर सुचारू रूप से ग्राम पंचायत पानी सप्लाई शुरू कर देती है तो लोगों की सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा।

ग्रामीणों का कहना है कि, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। गांव में सरपंच की दादागिरी इतनी है कि, कोई व्यक्ति अगर शिकायत भी करता है तो मामले को दबा दिया जाता है। हमारी बड़ी रामगढ़ में हमें जल्द से जल्द पानी मिलना चाहिए। अगर सरकार ने यहां टंकी निर्माण की है तो इस तरह से टंकी बंद नहीं होनी चाहिए। और जल्द ही इसको पंचायत सुधार करवा कर गांव में पानी सप्लाई करवाने का कष्ट करें यह मांग ग्रामीणों ने की है।

मामले में भेरूगढ़ ग्राम पंचायत के सचिव एकम कटारा ने बताया कि, विद्युत व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। अभी नई केबल लाइन डाली जा रही है जैसे केबल का काम पुरा होता है सुचारू रूप से पानी सप्लाई किया जाएगा।

बहुउददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्या.(बी.पेक्स) बरवेट

क्रमाक/2025-26/1/सा. सभा — दिनांक 08/09/2025

वार्षिक साधारण आम सभा

मान्यवर महोदय,

बहुउददेशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्या. (बी.पेक्स) बरवेट शाखा-सारंगी के समस्त सदस्यों को सुचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 24/09/2025 वार बुधवार को दिन के 12:00 बजे संस्था कार्यालय भवन बरवेट पर आयोजित की जावेगी। अतः नियत दिन व समय पर उपस्थित होने का कृष्ट करें।

उपरोक्त दिनांक 24/09/2025 को यदि नियत समय पर साधारण सभा के लियें गणपुर्ति नही हुई तो साधारण सभा स्थगित की जाकर उसी दिन व समय पर नियत समय के आंधे घंटे पश्चात वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्पन्न की जावेगी। जिसमें गण पुर्ति आवश्यक नही होगी।

प्रबंधक
बहुउददेशीय प्रा. कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्या. (बी.पेक्स) बरवेट

विषय सुची :-

1. वर्ष 2024-25 के वार्षिक पत्रक को स्वीकृत व पुष्टि करने बाबद ।
2. वर्ष 2023-24 एंव 2024-25 के आडिट नोट की तामिली प्रतिवेदन की पुष्टि करना।
3. गत आमसभा की पुष्टि करने बाबद ।
4. प्रबंधकारिणी की मिटिंग की पुष्टि करने बाबद।
5. संस्था का आगामी वर्ष 2025-26 के लिये अनुमानित बजट स्वीकृत करना।
6. वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट से अधिक हुई व्ययों की पुष्टि करना।
7. संस्था की अधिकतम ऋण सिमा निर्धारण करने बाबद ।
8. अन्य विषय प्रशासक महोदय की आज्ञा से।

प्रबंधक
बहुउददेशीय प्रा. कृषि साख, सहकारी सोसायटी मर्या. (बी.पेक्स) बरवेट

रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ

माही की गूंज, करवड़।

झाबुआ जिले के ग्राम करवड़ में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रक्तदान शिविर महा अभियान का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद करवड़ के नेतृत्व में संपन्न हुआ रक्तदान शिविर में कुल 27 पुरुष एवं तीन महिला ने शिविर में रक्तदान किया यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर करवड़ में तेरापंथ सभा भवन में आयोजित हुआ आज देश भर में 2000 से अधिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ जिसमें चार लाख से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष पीयूष मंडोत ने बताया कि ग्राम में 2 से 3 बार मेगा ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया जिसमें अरुण सब श्री माल उमेश श्रीमाल अरुण श्रीमाल जयेश मंडोत ऋतुराज मंडोत ग्रामीणों के द्वारा डॉक्टरों की टीम में उपस्थित चिकित्सा अधिकारी विमल सिंगाड़ सी एच ओ अशोक पाटीदार लैब टेक्नीशियन केसर सिंह मैंड़ा लैब टेक्नीशियन दिनेश परमार लैब टेक्नीशियन करण सिंह भूरिया नर्सिंग ऑफिसर सोनम मचार चिंतामणि मुलेव की उपस्थिति में ब्लड डोनेशन का सफल आयोजन किया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित काकनवानी जिला झाबुआ (म.प्र)

पंजीयन ऋमांक 198-24-031976

ऋमांक/सभा/2023-24 — दिनांक-10.09.2025

वार्षिक साधारण आमसभा का एजेण्डा

बहुउद्देशी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित काकनवानी के समस्त अंशाधारी सदस्यों महानुभावों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 24-09-2025 बुधवार को संस्था कार्यालय भवन पर दिन को दोपहर 12:00 बजे प्रशासक महोदय की अध्यक्षता में संपन्न की जा रही है। जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है।

नोट :- साधारण सभा की बैठक के लिए 1/10 अथवा 50 सदस्य जो भी कम हो कि गणपूर्ति के पश्चात आमसभा उसी दिनांक व स्थान पर 1 घंटे पश्चात संपन्न की जावेगी।

विषय सूची :-

1. गत वर्ष 2024-25 आमसभा की पुष्टि करने बाबद विचार।
2. संस्था का वर्ष 2024-25 के आय-व्यय पत्रक,व्यापारिक पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, पत्रक को स्वीकृत करने बाबद विचार।
3. संस्था का आगामी वर्ष 2025 26 के लिए अनुमानित बजट स्वीकार करने बाबद विचार।
4. वर्ष 2025-26 को स्वीकृत बजट से अधिक हुई व्यायों की पुष्टि करने बाबद विचार।
5. अन्य विषय प्रशासक महोदय की पूर्वानुमति से।

संस्था के वर्तमान उप नियम ऋमांक 26 के प्रावधान अनुसार सम्मेलन की बैठक की जावेगी। यदि एक उत्तर तिथि को 12:00 बजे गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक के नियम के अंतर्गत आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी जावेगी और गणपूर्ति कोरम के अभाव में स्थगित साधारण सभा उसी दिन उसी स्थान पर आधे घंटे के बाद दोपहर 12:30 बजे प्रारंभ होगी।

कृपया निर्धारित दिनांक एवं समय पर उत्तर साधारण सभा में भाग लेने की कृपा करें।

प्रशासक
बहुउददेशी प्राथमिक कृषी साख सेवा सहकारी संस्था मर्या, काकनवानी

संस्था प्रबंधक
बहुउददेशी प्राथमिक कृषी साख सेवा सहकारी संस्था मर्या, काकनवानी

संपादकीय

वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों ने ही स्वागत किया है।

एक संवेदनशील संतुलन बनाते हुए न्यायालय ने अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है। जिसमें एक वह खंड भी शामिल है, जो यह निर्धारित करता है कि पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले लोग ही किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। हालांकि, न्यायालय ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि 'अनुमान हमेशा किसी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होता है।' बहरहाल, सत्तारूढ़ भाजपा इस बात से राहत महसूस कर रही है कि अब इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किए जाने का खतरा नहीं है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि इस कानून के पीछे विभाजनकारी एजेंडा उजागर हुआ है। दरअसल, सरकार ने अप्रैल में लागू किए इस कानून को देशभर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के लिये एक 'धर्मनिरपेक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह' व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से लागू करने की बात कही थी। निस्संदेह, वक्फ बोर्डों पर वर्षों से लग रहे भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, अतिक्रमण, संपत्ति की अवैध बिक्री और हस्तांतरण आदि के आक्षेपों को देखते हुए, प्रशासन में सुधार के लिये नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों को यह आशंका रही है कि तथाकथित सुधारों का दुरुपयोग वक्फ मामलों में हस्तक्षेप करने और यहां तक कि संपत्तियों को जब्त करने के लिये किया जा सकता है। उनकी दृष्टि में एक विवादास्पद प्रावधान केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से संबंधित रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे सदस्यों की संख्या को सीमित करने का प्रयास किया है। कहा गया कि कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन न हो सके।

दरअसल, विगत में विपक्ष आशंका जताता रहा है कि यह अधिनियम ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है और सांप्रदायिक सद्भाव के लिये खतरा बन सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायालय का अंतिम आदेश कानून से जुड़ी ऐसी तमाम आशंकाओं का समाधान कर सकेगा। देश के मौजूदा परिदृश्य में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये वक्फ की समृद्ध क्षमता का दोहन करने पर राजनीतिक और धार्मिक सहमति बनाने की आवश्यकता है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत का फैसला पूरी तरह से तार्किक आधार रखता है, जिसे संतुलन के हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही है। जिससे मुस्लिम पक्ष की कतिपय आशंकाओं को दूर करने का ही प्रयास हुआ है। निस्संदेह, शीर्ष अदालत द्वारा किए गए संशोधन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने उन प्रावधानों पर भी रोक लगायी है, जो जिलाधिकारी या सरकारी अधिकारी को यह तय करने की शक्ति देते थे कि कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। दरअसल, शीर्ष अदालत का मानना था कि जिलाधिकारी कार्यपालिका का अंग ही होता है। अगर उसे यह शक्ति दी जाती है तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। जिसके मूल में यह सोच रही है कि लोकतंत्र के तीन आधारभूत स्तंभों विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का संतुलन कायम रह सके। जाहिर है कि एक स्तंभ को अधिक शक्तियां मिलने से उसके निरंकुश व्यवहार करने की आशंका बनी रह सकती है। इसके अलावा वक्फ करने के न्यूनतम पांच बरस तक इस्लाम के अनुयायी होने वाले प्रावधान के सत्यापन हेतु राज्य सरकारों से नियम बनाने की जरूरत भी बतायी और तब तक इस प्रावधान पर रोक की बात कही। इस दिशा में राज्य सरकारों को विषय की संवेदनशीलता के मद्देनजर कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल, इस मुद्दे पर विपक्ष व कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध का जो आधार रहा है, उन मुद्दों को संवेदनशील ढंग से संबोधित करने का प्रयास शीर्ष अदालत ने किया है। दरअसल, अदालत ने विधायिका की सीमाओं में हस्तक्षेप किए बिना न्यायिक तार्किकता को प्राथमिकता दी है।

कटुता-क्रिकेट और बेहतर रिश्तों की उम्मीद

विश्वनाथ सचदेव

भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में कुछ भी कहने से पहले यह कहना चाहता हूं कि एशिया कप के लिए दुबई में हुआ इन दोनों देशों का मुकाबला मैंने देखा था और यह देखकर बहुत खुश हुआ था कि भारत यह मैच बड़ी शान से जीत गया। सच कहूं तो यह मैच मैंने क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले के लिए नहीं, भारत को जीतने के लिए खेलते हुए देखने के लिए देखा था। जिस भी भारतीय ने इस मैच को देखा होगा, निश्चित रूप से वह भारत को जीतते हुए देखना चाहता होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि खेल खेल के लिए भी देखा जाता है, शायद देखा भी इसीलिए जाना चाहिए। लेकिन जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो बात खेल तक ही सीमित नहीं रहती, यह भी सच है। दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए यह सही भी है। लेकिन ग़लत यह भी नहीं है कि ऐसे खेलों का एक उद्देश्य रिश्ते सुधारना भी होता है।

दुबई का यह मैच जिन स्थितियों में खेला गया, उनमें यह उम्मीद करना कि इससे रिश्ते सुधर जायेंगे, सही नहीं लगता। हमने यह भी देखा कि खेल के लिए सिक्का उछालते वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाये थे और खेल समाप्त होने के बाद भी खिलाड़ियों के लिए हाथ मिलाने की परंपरा को भी नहीं निभाया गया। पाकिस्तान के कप्तान ने तो आगे बढ़कर हाथ मिलाना चाहा था, पर हमारे कप्तान और हमारी सारी टीम ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। और यह सही भी था। पहलगाम में पाकिस्तान की शह पर, और पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवादियों ने मनुष्यता को कलंकित करने वाला जो घिनौना कार्य किया था, उसके बाद भारत के खिलाड़ियों द्वारा ऐसा कुछ न किया जाना हैरान करने वाली बात होती। हमारी टीम के कप्तान ने इस विजय को 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम देने वाले हमारे जांबाज सैनिकों और पहलगाम में शहीद हुए भारतीय पर्यटकों के परिवारों को समर्पित किया है। यह सब यही बताता है कि हाथ न मिलाने वाली यह घटना अनायास नहीं हुई थी, निश्चित रूप से पहले इस बारे में निर्णय ले लिया गया होगा।

देश में कुछ लोगों को, या कइयों को, इस निर्णय से शिकायत है। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना है कि 'खून और क्रिकेट साथ-साथ नहीं चल सकते'। बात ग़लत भी नहीं लगती। पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, और जो कुछ कर रहा है, वह भुलाने या क्षमा करने लायक नहीं है। इसकी सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए। 'ऑपरेशन सिंदूर' इसी सज़ा का एक हिस्सा है। यह भी सही है कि हमारी यह कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई। हमने अभी इस 'ऑपरेशन' को 'स्थगित' ही किया है। पता नहीं, इस स्थगन का क्या मतलब है और कार्रवाई का अगला कदम कब उठाया जायेगा। यह हमारी सरकार को तय करना है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमें यानी देश के नागरिकों को तय करना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो कुछ किया, उससे उपजा गुस्सा आसानी से, और जल्दी से, शांत नहीं हो सकता। देश में गुस्सा है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान दोनों देशों के रिश्तों के बारे में जो कुछ कर रहा है, उसे विवेकहीनता के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। हमने सारी दुनिया को यह बात बताई है, और अधिकांश देशों ने हमारे दृष्टिकोण को समझा- स्वीकारा है।

पाकिस्तान कब समझेगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक विवेकशील देश होने के नाते हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने इस पड़ोसी देश को समझाएं कि वह जो कर रहा है वह हर दृष्टि से ग़लत है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 'हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते'। इस बात को समझने की आवश्यकता हैकृऔर पाकिस्तान को समझाने की भी। वाजपेयी जी ने यह कोशिश की थी। बशीर बद्र का एक शे'र भी सुनाया था उन्होंने पाकिस्तानियों कोकृ'दुश्मनी जम कर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे/ फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हों।' यह शर्मिंदगी पाकिस्तान को समझनी चाहिए।

बहरहाल, मुल्कों की दुश्मनी को अनंतकाल के लिए लटकाये नहीं रखा जा सकता। आखिर हम चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही रहे हैं। तरेसठ साल पहले, 1962 में, चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंप था। उसके बाद हमारी ज़मीन के बड़े हिस्से पर उसने कब्जा कर रखा है। अभी हाल तक वह भारत-विरोधी गतिविधियां करता रहा है। इस सबके बावजूद हम चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त और दुश्मन स्थाई नहीं हुआ करते, देशों को समय और स्थितियों के अनुसार अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं। हां, इस बारे में सावधानी बरतना एक महत्वपूर्ण शर्त है। गले मिलना कतई ज़रूरी नहीं है। 'जरा फासले से मिला करो' वाली नसीहत याद रखनी चाहिए। पर फासला इतना भी न हो जाये कि उसे पाटा न जा सके अथवा पाटने की कोशिश ही न हो।

दुहराया जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, उसका समर्थन किसी भी दृष्टि से नहीं किया जा सकता। क्रिकेट मैच में जीत के बाद हमारी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत से रिश्तों के संदर्भ में उसे अपनी दृष्टि और नीतियां दोनों, बदलनी होंगी। उसे यह भी समझना होगा कि पड़ोसी सबसे नज़दीकी रिश्तेदार होता है। यह बात सबको याद रखनी चाहिए। इस सब में वे भी शामिल हैं जो आज यह मान रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। पहली नज़र में यह बात भले ही सही लगती हो कि पहलगाम जैसा अमानवीय काम करने-कराने वाले देश के साथ खेलों या कला के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, पर यह बात याद रखनी चाहिए कि रिश्ते जोड़ने वाली राह बहुत लंबी होती है। इस लंबी राह में थकना भी स्वाभाविक है। पर थकने के डर से चलना भी तो नहीं रुक सकता न? चलना तो पड़ेगा। पड़ोसी के साथ क्रिकेट खेलने को इस चलने के एक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

जैसा कि शुरू में कहा, मैंने दुबई में खेला गया भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट का मुकाबला देखा हैदूमैं पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहता था। मैंने यह भी देखा कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाये। अपनी टीम के कप्तान को यह कहते हुए देखना भी अच्छा लगा कि टीम ने इस विजय को 'ऑपरेशन सिंदूर' को कामयाब बनाने वाले सैनिकों और पहलगाम में शहीद होने वाले पर्यटकों के परिवारों को समर्पित किया है।

जो ग़लत हुआ उसका दुख और गुस्सा अपनी जगह सही है, पर ग़लत को सही करने की आवश्यकता को भी समझना ज़रूरी है। सुना है, इस और ऐसे मैचों से हमारे क्रिकेट संघ को कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता है। मैं नहीं जानता कितना लाभ होता है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उस रात दुबई के उस मैदान में भारत और पाकिस्तान के समर्थक अपने-अपने देश के झंडे लेकर अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। झंडे लहरा रहे थे, एक-दूसरे से टकरा नहीं रहे थे। खिलाड़ियों ने भले ही एक-दूसरे से हाथ न मिलाये हो, लेकिन पाकिस्तान के झंडे वाली एक युवती को भारत का झंडा लहराते पड़ोसी दर्शक को बधाई देते हुए देखना एक उम्मीद जगाने वाला पल था!

लाज होती तो भिखारी क्यों होते

भिखारी होना बहुत मुश्किल काम है और ऐसा भिखारी होना तो बहुत ही मुश्किल काम है जो खुद को टॉप क्लास अमीर समझता है।

पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान को अमीर देशों की बहुत चिंता रहती है क्योंकि भीख यहीं से मिलती है। इस्राइल ने यमन में, सीरिया में बमबारी की है, पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं हुई। कतर में इस्राइली बमबारी के बाद पाकिस्तान चिंतित हो उठा। कतर दाता देश है, पाकिस्तान भिखारी है, दाता की चिंता करनी पड़ती है। भिखारी को कई बातें भूलनी पड़ती हैं। इस्राइल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी देश है। पाकिस्तानी नेता हंस कर चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस्राइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है।

अमेरिका के पैर पकड़कर पाकिस्तान दो-चार मिलियन डालर इधर-उधर से बटोर लाता है। ट्रंप का नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करता है पाकिस्तान, इन्ही ट्रंप के समर्थन से इस्राइल कतर की तुड़ाई करता है। पाकिस्तान फिर कहता है कि ट्रंप को नोबल दो। ट्रंप समर्थित इस्राइल मार तुड़ाई मचाये हुए है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि जिसके लिए शांति का नोबल मांगा, उसका समर्थक देश ही कतर में अशांति मचाये हुए है। पर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका से कह दे कि हे नोबल शांति के इच्छुक ट्रंप, इस्राइल से कहिये कि हमारे एक दाता देश कतर में शांति करवा दे। पाकिस्तान की औकात नहीं कि यह बात ट्रंप से बोल दे। वहीं से भीख मांगनी है। पाकिस्तान सतत भिखारी देश है, उसकी हिम्मत सिर्फ आतंक मचाने की है।

भिखारियों के जत्थे के जत्थे चले आते हैं। दुनिया के भिखारियों की जनसंख्या का आकलन हो, सबसे ज्यादा अनुपात पाकिस्तानियों का निकलेगा। पाकिस्तान से दुनियाभर में तीन प्राणी जाते हैं एक भिखारी, दो आतंकी और तीसरे गधे। पाकिस्तान गधों का भारी मात्रा में निर्यात करता है।

सच बोलने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है।

पाकिस्तान इस्राइल को मान्यता नहीं देता। यह बात इस्राइल के लिए राहत की बात है। जिन देशों को पाकिस्तान मान्यता देता है, वहां पाकिस्तानियों का आना जाना होता है। जहां पाकिस्तानियों का आना जाना है, वहां बहुत तनाव हो जाता है। अरब देश परेशान हैं कि पाकिस्तान से

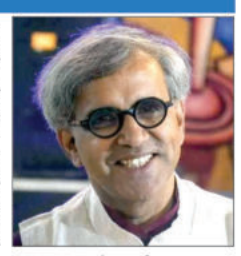

आलोक पुराणिक

कतर पहुंचे जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो कतर के लोग यही सोचकर परेशान हो गये कि फिर आ गये, अब कुछ लेकर ही जायेंगे। विकट भिखारी टलता नहीं है, जब तक कुछ ले न ले। पड़ा ही रहता है कि कुछ ला, तब ही जाऊंगा। भिक्षाटन मुश्किल काम है। बेशर्मी बहुत चाहिए। पर शर्म होती तो भिखारी क्यों होते जी।

अमीरों को 100 फीसदी टैक्स छूट : काले धन को सफेद करने की सुविधा

भारत में आम आदमी भारी टैक्स देने को मजबूर है। जबकि बड़े-बडे उद्योगपतियों को बिना टैक्स दिए करोड़ों रुपए की कमाई और काली कमाई को सफेद करने के लिए नियमों में संशोधन कर विशेष अवसर मिल रहा है। सरकार ऐसी नीतियाँ बना रही है, जो सीधे तौर पर अमीरों को फायदा पहुंचा रही हैं। जबकि देश के गरीब से गरीब नागरिकों से भारी टैक्स वसूल किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स के कारण अपने बच्चों को पोषण आहार भी नहीं दे पा रहा है वहीं शिक्षा देने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवारों को आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। वहीं अमीर बिना कोई टैक्स दिए हर साल करोड़ों-अरबों रुपए सरकार की टैक्स नीति के कारण यहां कमाई कर रहे और विदेश में निवेश कर रहे हैं। अमीरों के लिए सरकार की दो योजनाएं सरकारी खजाने के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रही हैं। एक योजना, जीएआर (जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल) और दूसरी गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी) योजना है। इन दोनों योजनाओं में बड़े-बड़े उद्योगपति और कारोबारी करोड़ों तथा अरबो रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं सरकार को टैक्स के रूप में 1 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। जीएआर के माध्यम से सरकार ने अल्टीमेट बेनिफिशरी ओनर (अंतिम लाभार्थी मालिक) का खुलासा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि बड़े उद्योगपति अपने निवेश के असली स्रोत को छुपाकर बड़ी आसानी से काला धन सफेद कर रहे हैं। पहले काले धन को संभालना मुश्किल होता था, लेकिन अब काला धन सफेद धन में परिवर्तित हो रहा है तथा इससे लगातार कमाई भी हो रही है। उदाहरण स्वरूप, अडानी समूह और चंदा कोचर के मामले में इस कानून के माध्यम से इसी तरह से लेन-देन किया गया। इससे साफ है, कि कानून के सहारे बड़े उद्योगपति बिना टैक्स चुकाए अरबों रुपये का लाभ कमा रहे हैं। दूसरी योजना, गिफ्ट सिटी, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर विदेशी निवेशकों और कंपनियों को ऐसा वातावरण दिया गया है, जहाँ वे 10 वर्षों तक पूरी तरह से टैक्स फ्री होकर व्यवसाय कर सकते हैं। जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आदि में छूट मिलती है। इस सिस्टम में कंपनियों को बस एक ऑफिस खोलना होता है। बिना कोई व्यापारिक गतिविधि किए भारी निवेश करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि रोजगार सृजन के बजाय, केवल टैक्स बचाने के लिए यह पैसा घुमाया जाता है। विदेश से जो धन भारत से भेजा गया था वही धन भारत लौटकर आ जाता है। सरकार को टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। वही कोई कारोबार ना होने से युवाओं को रोजगार और नौकरी भी नहीं मिलती है।

सरकार ने केवाईसी नियमों मे भी ढील दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनशोधन आसानी से होता रहे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के स्थान पर अब इन दो कानूनों के कारण बिना टैक्स दिए करोड़ों रुपए का अवैध रूप से लेनदेन हो रहा है। विदेशी निवेश के नाम पर जो पैसा टैक्स हेवन देशों में जाता है उसका उद्देश्य केवल कर बचाना होता है, नाकि वास्?तविक निवेश के रूप में होता है। सरकार ने बड़े-बड़े अमीरों को टैक्स न देना पड़े शायद इसी के लिए योजना बनाई है। भारत में टैक्स के लिए गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून है, बड़े-बड़े धन्ना-सेठ और कारोबारियों के लिए अलग कानून है। सरकार पिछले कुछ वर्षों से मनी बिल के तहत समय-समय पर नियमों मे बदलाव कर देती है। जो नए नियम बनाकर लागू किये गए हैं, वे संसद में पेश भी नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के जरिए नियमों में बदलाव किया गया है।

इस असमान व्यवस्था का सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। आम जनता से सैकड़ों किस्म के टैक्स और शुल्क वसूल किए जाते हैं। टैक्स एवं शुल्क के आतंक से आम जनता परेशान है। वहीं बड़े कारोबारी उद्योगपति और भ्रष्ट कमाई वाले टैक्स-फ्री होकर भी रोजाना काले और सफेद धन को दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ा रहे हैं। भारत का पैसा विदेशों में ले जाकर निवेश कर रहे हैं। भारत में जो अरबपति हैं उनके परिवार के कई लोग विदेश में जाकर नागरिकता ले रहे हैं। भारत की पूंजी को विदेश में निवेश कर रहे हैं। अब समय आ गया है, इन भ्रष्ट और अनियमित अनैतिक योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। देश के विकास का लाभ तथा सभी वर्गों के लिए एक समान टैक्सेशन हो। समाज के सभी वर्गों तक सरकार के नियम कानून और सरकारी खजाने का लाभ हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचे इस दिशा में काम करने की जरूरत है। संविधान इस तरह से अलग-अलग कानून बनाने की अनुमति भी नहीं देता है। न्यायपालिका की चुप्पी और अनदेखी की अब खुलेआम आलोचना भी होने लगी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को इस मामले में गंभीरता के साथ विचार करते हुए अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। पिछले एक दशक में जिस तरीके से गरीबों और अमीरों के बीच में असमानता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। उन सब पर रोक लगाने की जरूरत है। ना कि उन्हें संरक्षण देने की। उपरोक्त दोनों कानून को तुरंत समाप्त किए जाने की जरूरत है। ताकि भ्रष्टाचार और आर्थिक घोटालों पर रोक लग सके।

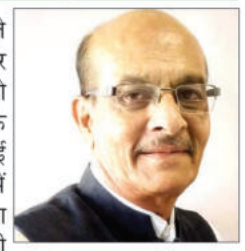

सनत कुमार जैन

ट्रायल कोर्ट को हाईकोर्ट का आदेशः भोपाल गैस त्रासदी मामले में देरी बर्दाश्त नहीं

माही की गूंज, भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 17 सितम्बर को भोपाल ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रकरण का शीघ्र निपटान करने और आरोपियों पर जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। इसमें यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन का नाम भी शामिल है।

यह आदेश भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया गया। सुनवाई के दौरान जब सरकारी पक्ष ने स्थगन की मांग की, तो मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफा की खंडपीठ ने कहा कि ÷हम 40 साल तक मामले को लंबित नहीं रख सकते।÷ अदालत के इस निर्णय से पीड़ितों में न्याय की नई उम्मीद जगी है।

ज्ञात हो कि दिसम्बर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस भीषण दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों प्रभावित हुए थे। आज भी पीड़ित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को गैस त्रासदी से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है, जिसे रजिस्ट्रार के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले की सुनवाई अब 5 अक्टूबर तक स्थगित की गई है।

वहीं समिति की ओर से दायर एक अन्य याचिका, जिसमें संबंधित जजों के तबादले, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई थी, को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

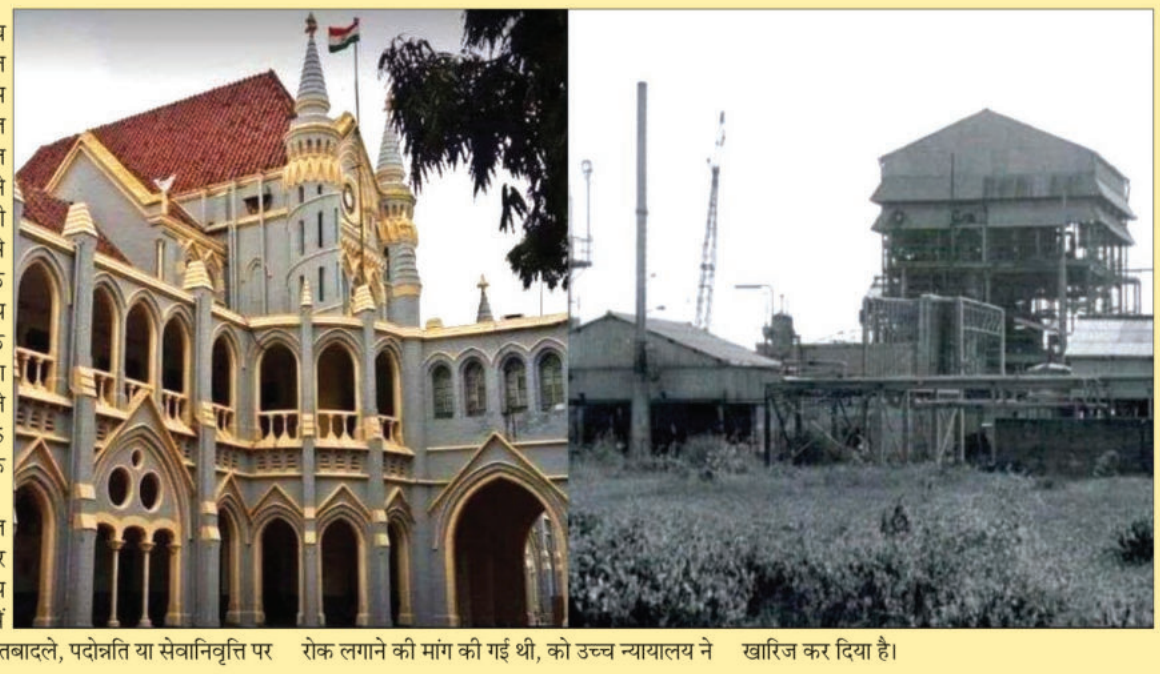

स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा का शुभारम्भ सोण्डवा विकासखण्ड में

माही की गूंज, आलीराजपुर।

17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक पूरे देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा स्वच्छोत्सव की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत सोण्डवा के जनपद सभागृह में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारम्भ किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष रेवली गरासिया, जनपद उपाध्यक्ष विक्रमसिंह भयड़िया, जनपद सदस्य ओपसिंह सोलंकी, अन्य जनप्रतिनिधि, जिला मुख्यालय से संदीप भोसले, हर्षल परलीकर, जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

विभिन्न पंचायतों से पहुँचे सरपंच एवं पंच सदस्यों ने स्वच्छता की शपथ ली। विकासखण्ड मुख्यालय से हाट बाजार तक स्वच्छता का संदेश पहुँचाते हुए रैली निकाली गई। इसके साथ ही सोण्डवा के हनुमान मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण जनों द्वारा श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की गई।

विश्वकर्मा जयंती उत्साह से मनाई गई

माही की गूंज, शाजापुर।

शाजापुर में बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शोभायात्रा निकाली गई और विश्वकर्मा सुथार समाज ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मरीजों को फल वितरण और पूजा-अर्चना शामिल थी।

सोमवारिया बाजार स्थित विश्वकर्मा मंदिर से शोभायात्रा प्रारंभ हुई। यह नाग-नागिनी रोड, नई सड़क, बड़ा चौक और छोटा चौक से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। यात्रा में ढोल-नगाड़ा और भजनों की धुन पर महिला-पुरुष व युवा नाचते-गाते हुए शामिल हुए।

स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में महिलाएं लाल साड़ी पहनकर शोभायात्रा में शामिल हुईं, जिन्होंने ÷एकजुटता÷ का संदेश दिया। पुरुष पारंपरिक सफेद कुर्ता-पायजामा एवं सांस्कृतिक वेशभूषा में नजर आए।

विश्वकर्मा सुथार समाज ने भी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। समाज जिलाध्यक्ष बालकृष्ण विश्वकर्मा के नेतृत्व में टीम और सदस्यों ने शासकीय भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए।

मंदसौर पुलिस ने पकड़ा एमडी ड्रग्स तस्कर गिरोह

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुल 150 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले हैं। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने प्रतापगढ़ रोड स्थित गोशाला के पास घेराबंदी कर विजय पिता पूनमचंद पाटीदार, निवासी चांदाखेड़ी थाना भावगढ़, जिला मंदसौर और भगत पिता नाथूलाल गुर्जर, निवासी नाहरगढ़, जिला मंदसौर को हिरासत में लिया। दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 150 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। यह एक खतरनाक नशीला पदार्थ है, जिसका उपयोग अवैध नशे के कारोबार में किया जाता है। बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। कोतवाली प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लाए थे और किसे देने जा रहे थे।

पकड़ी ढाई लाख की अवैध शराब

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के बिलपांक थाना पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस को देखते ही शराब से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी लेकर चालक और उसका साथी भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया तो कच्चे रास्ते में चालक और साथी गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए।

रतलाम पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिलपांक थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी अयूब खान, पुलिस चौकी धराड़ और सायबर सेल की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 43 जेड 0483 में दो व्यक्ति अवैध शराब और बियर लेकर नलकुई-भाटी बड़ौदिया मार्ग पर खड़े हैं।

सूचना पर टीम बनाकर पुलिस ने घेराबंदी की। मौके पर पहुंचते ही पुलिस को देखते ही वाहन चालक और उसका साथी वाहन लेकर भागे। पीछा करने पर वाहन को नलकुई गांव पार कर कच्चे रास्ते पर रोका गया। इस दौरान दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य जांच, रक्तदान शिविर

माही की गूंज, खंडवा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत जिले में कई कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। ओंकारेश्वर में प्रभारी मंत्री का दौरा स्थगित हो गया, लेकिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल सुबह 8 बजे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे और मंदिर परिसर व ब्रह्मपुरी घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई। सांसद पाटिल ने स्वच्छता सेवा दूतों को सम्मानित किया। इसके बाद वृद्धा आश्रम पहुंचे और वृद्धजनों का सम्मान कर आशीर्वाद लिया।

ओंकारेश्वर के बाद सांसद पाटिल पुनासा के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया। इसके साथ नगर परिषद पुनासा द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

नर्मदानगर में एनएचडीसी परियोजना परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय नागरिकों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर इस अभियान में योगदान दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पुनासा में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां जांच और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। जिले के सभी शासकीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए।

पड़ोस के घटनाक्रम पर रहे पैनी नजर भारत की

पिछले हफ़्ते की शुरुआत में नेपाल में क्रांति इतनी अचानक, इतनी त्वरित और इतनी नाटकीय थी कि भारत तक अचंभित रह गया। जब पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली की सशस्त्र पुलिस ने युवा छात्र प्रदर्शनकारियों पर, जिनमें स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहने बच्चे भी शामिल थे, निर्ममता से गोलियां चलाईं, तो भारतीय अधिकारियों को तुरंत अहसास हो गया कि पुरानी व्यवस्था ढह रही है। वे तो 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओली की भारत यात्रा की तैयारियां कर रहे थे। वे स्तब्ध थे कि इससे एकदम पहले ही घटनाओं ने अचानक बड़ा मोड़ ले लिया।

भारत-नेपाल संबंधों की खासियत यह है कि यह इतना घनिष्ठ, इतना गहरा और अटूट है कि भारत के रिश्ते किसी अन्य देश के साथ इस जैसे नहीं हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ साल पहले तराई और भारत के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के बीच इस 'रोटी-बेटी' के रिश्ते को दिल्ली के अभिजात वर्ग को बताकर चौंका दिया था, लेकिन यह मुहावरा नेपाल और भारत के बाकी हिस्सों के लिए भी उतना ही सच है। नेपाल के अभिजात वर्ग और सर्वहारा वर्ग- 'बाहुन' और 'छेत्री', पहाड़ों के ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, और निचले एवं मैदानी इलाकों के अन्य जातियों के लोग - भारत में विवाह करते आए हैं या बसे हैं और काम करते हैं और भारतीय भी इसी तरह से वहां रहते-काम करते हैं। रिश्तेदारी के बंधन पीढ़ियों को नया रूप देते रहे। अगर आप पटना से जनकपुर तक गाड़ी से जाते हैं, तो खुली सीमा पार करते समय कोई भी आपकी तरफ दुबारा गौर तक नहीं करता।

आप दलील दे सकते हैं कि यह बात तो भारत के हर पड़ोसी के लिए भी सच है, कि जातीयता, धर्म और संस्कृति -भूगोल एवं संप्रभुता- दोनों से, परे होती हैं। निश्चित रूप से, यह उन तीन देशों के लिए विशेष रूप से सच है जिनके लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कब्जाने के विरुद्ध अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है- 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और अब नेपाल। इन सभी क्रांतियों में छोटे-बड़े अंतरों के बावजूद, मौलिक समानता अभेद है। लोग इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि वे उस नेतृत्व से तंग आ गए, जिन्हें उन्होंने वोट डालकर चुना था लेकिन वे उन्हें ही गले में फंदा डालकर मवेशियों की तरह हांकने लगे।

काठमांडू में चीज़ें तेज़ी से बदलीं। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा चुकी है और संसद भंग कर दी गई है। तथापि, सत्ता के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे संकेत हैं कि नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेलकृजिन्हें भारत-नेपाल विशेष संबंधों के चलते पिछले दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना में 'ब्रदर जनरल' का मानद पद प्रदान किया गया थाकृअपनी स्थिति मज़बूत करना चाहते हैं और संभवतः राजशाही समर्थक राजनेताओं के पक्ष में झुकाव रखते हैं। यह कभी न भूलें कि दशकों तक जब नेपाल के राजा शीर्ष पर थे, तत्कालीन शाही नेपाल सेना का हर सुबह पहला घोष था 'श्री पंच को सरकार जय जय हो' !

यह झटका सबसे हैरानीजनक वर्ग से आया है। कहा जाता है कि सेना प्रमुख चाहते थे कि राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल इस्तीफा देकर 'नव नेपाल' का मार्ग प्रशस्त करें, लेकिन पौडेल ने जवाब में कुछ इस तरह कहा 'आप मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन मैं लोकतांत्रिक बने रहना नहीं छोड़ूंगा'। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और शेर बहादुर देउबा जैसे अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ, पौडेल को भी कुछ दिनों के लिए सेना की सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनके आधिकारिक आवास, शीतल निवास, में वापस भेज दिया गया।

फिर कुछ अनाम, चेहराविहीन जेनरेशन ज़ेड के नेता हैं, हो सकता है जिनके गुट पिछले इन कुछ दिनों से आपस में झगड़ रहे होंगे, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण अगले कदम पर अड़े हुए हैंः राजशाही की वापसी कतई नहीं। और नेपाल का संविधान, जो पिछली क्रांति, 2006 के जन आंदोलन के बाद अंततः 2015 में अस्तित्व में आया था,उसे खारिज नहीं किया जा सकता। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नेपाल के दो सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी, भारत और चीन, क्या सोच रहे हैं। चीन ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर 'बारीकी से नज़र' रख रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने काठमांडू को तहस-नहस करने वाली हिंसा को 'दिल दहला देने वाली' बताया है। हालांकि, दिल्ली में किसी भी अन्य राजनीतिक दल की चुप्पी गौरतलब है - उन सभी को चुप रहने के लिए कहा गया है, जो कि होना भी चाहिए। भारत इस क्षेत्र के इस बेहद महत्वपूर्ण क्षण के साथ बहुत सावधानी से बरत रहा है।

कहा जा रहा है कि नेपाल में भारत प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक ताकतों का समर्थन करना जारी रखेगा, जैसा कि उसने अतीत में हमेशा किया है। साल 2006 के जन आंदोलन के दौरान भी भारत के तत्कालीन विदेश सचिव श्याम सरनकृऔर द ट्रिब्यून के एक स्तंभकारकृ ने पारंपरिक लीक से हटकर घोषणा की थी कि भारत 19 दिनों तक चले समतावादी विरोध के समर्थन में है। अप्रैल 2006 की उस आधी रात को, मैंने काठमांडू की सड़कों पर अविश्वसनीय खुशी देखी क्योंकि भारत ने सही चुनाव किया था। इसने नेपाल की राजशाही के अंत की घोषणा की जिसने 1768 से नेपाल और खुद को एकजुट रखा था, जब पृथ्वी नारायण शाह ने युद्धरत राजाओं के बीच सुलह कर एकता बनाई थी।

आज एक और ऐसा ही क्षण हमारे समक्ष है और हमें वर्तमान से निबटने के लिए अतीत से कई सबक सीखने होंगे। प्रथम, नेपाल की उथल-पुथल भारत को अपने पड़ोसियों से और ज्यादा नज़दीकी जुड़ाव बनाए रखने की अहमियत याद दिलाए। दूसरा, भले ही भारत की विशिष्ट विदेश सेवा अधिकारियों को पश्चिम के जलस्रोतों का पानी अधिक सुहाता हो लेकिन बागमती, कोसी और महाकाली के जल जैसा कुछ नहीं है, जिसे गहराई से ग्रहण कर ज्ञान एवं संस्कृति, दोनों को आत्मसात किया जा सकता है।

ज्योति मल्होत्रा

और तीसरा, न केवल इस क्षेत्र में, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत एक आदर्श उदाहरण है- अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, अपने पूर्ववर्ती कई नेपाली राजनेताओं की तरह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं - और उन्हें इसी रूप में देखा जाना जारी रहे।

शेष दक्षिण एशिया के साथ-साथ नेपाल को भी भारत के ध्यान में सर्वप्रथम और केंद्र में रखना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमसे काफी छोटे देश भारत के कुछ प्रांतों से भी छोटे हैं या बहुत ही छोटे हैं। सीधा सच यह है कि भारत को फिर से 'सभी नावों को अपने साथ ऊपर उठाना' वाले सिद्धांत पर लौटना होगा और इन संप्रभु राष्ट्रों के साथ बराबरी का रिश्ता बनाना होगा, जिनके पास पाने के साथ-साथ देने के लिए भी बहुत कुछ है।

फिर, एक चौथा कारण भी है। भारत का राजनीतिक वर्ग भी दक्षिण एशिया को भूल गया है। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता डीपी त्रिपाठी और सीताराम येचुरी एवं प्रकाश करात जैसे वामपंथी नेता मिलकर नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति के पक्ष में खड़े थे। हालांकि, आज के राजनेता कहीं और देखना पसंद करते हैं।

सौभाग्य से, भारत-नेपाल बंधन इतना मज़बूत है कि रिश्ते अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन अगर उदासीनता जारी रही, जैसा कि कभी-कभी होने का खतरा होता है, तो डर यह है कि यह कुछ हद तक कमजोर होने लगेगा।

40 से ज्यादा परिवारों को अतिक्रमण का नोटिस

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी के पास स्थित तलून खुर्द गांव में 40 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने अतिक्रमण का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो उन पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना और सिविल जेल की कार्रवाई हो सकती है।

बड़वानी 2 तहसीलदार कार्यालय की ओर से जारी इस नोटिस में बताया गया है कि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार गांव की भूमि नंबर 33/1 पर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

नोटिस मिलने के बाद परेशान ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर के पास जनसुनवाई में पहुंचे और एक आवेदन सौंपा। ग्रामीण सुनील बामनिया ने कहा कि वे 30-40 साल से यहां रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला, जिससे करीब 35 पक्के मकान भी बन चुके हैं। एक अन्य ग्रामीण शिवकन्या बाई ने बताया कि वे मज़दूरी कर जीवनयापन करती हैं और इस नोटिस से उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है।

गांव के सरपंच पति लोकेश नरगावे ने इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला, जो साबित करता है कि यह कोई अतिक्रमण नहीं है।

लोकेश नरगावे ने कहा कि प्रशासन इन लोगों को बेघर नहीं कर सकता और वे खुद उनके समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वे इस मामले में कलेक्टर, विधायक, सांसद और अन्य नेताओं से मिलकर अपनी बात रखेंगे। इस मामले में जब नायब तहसीलदार सोनू गोयल से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया।

झमाझम बारिश, शहर में बादल छाए

माही की गूंज, खंडवा।

बुधवार देर शाम मोरटक्का क्षेत्र में तेज बारिश हुई। पानी इतनी तेज़ी से गिरा कि राजमार्ग पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का असर धनगांव और ओंकारेश्वर तक रहा। वहीं, एक दिन पहले पंधाना और खालवा क्षेत्र में भी बारिश दर्ज की गई थी। शहर में पिछले दो दिनों से बादल छाए हुए थे लेकिन पानी नहीं गिरा था। इसके बावजूद जिले में दो दिन के भीतर लगभग तीन इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई है।

इधर, फसलों की बात करें तो सोयाबीन, मक्का और कपास की फसल तैयार हो गई है। मौसम को देखते हुए किसानों ने कपास तुड़ाई शुरू कर दी है। वहीं, पक चुकी सोयाबीन की कटाई भी अगले सप्ताह से शुरू होगी। लेकिन किसान चिंतित हैं क्योंकि फसल कटाई के समय बारिश की संभावना बनी हुई है। ज्यादा परेशानी जल्दी पकने वाली सोयाबीन की किस्मों को है।

मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह के अंत तक मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विशेषज्ञ डॉ. सौरव गुप्ता के मुताबिक जिले में 25 सितंबर से तेज बारिश के आसार हैं। फिलहाल अगला सप्ताह निर्णायक रहेगा। मानसून की सक्रियता अक्टूबर की शुरुआत तक रहेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून विदा लेगा। हालांकि, जमीन की उमस और स्थानीय तंत्र के कारण भी बारिश हो सकती है।

विश्वकर्मा पूजन समारोह जुलूस के साथ संपन्न

माही की गूंज, खवासा।

नया गुजराती लोहार समाज के जिलाध्यक्ष शैतानमल लोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि, लोहार समाज द्वारा प्रतिवर्ष अलग-अलग गांवो में विभिन्न आयोजन विश्वकर्मा जयन्ति पर किया जाता है। इस वर्ष खवासा में बुधवार को विश्वकर्मा पूजन महासमारोह का आयोजन रखा गया। जिसमें समाज के जिले के साथ अन्य जिलों से भी नया गुजराती लोहार समाज के समाजजन समारोह में सम्मिलित हुए। श्री लोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि, आज खवासा स्थानिक चमत्कारी बजरंगबली मंदिर से भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के साथ जुलूस निकाला गया। जिसमें समाजजनों के साथ स्थानीय आमंत्रित गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। एवं उक्त जुलुस मंदिर से पूरे ग्राम भ्रमण के साथ महिला, पुरुष व युवाओं ने नृत्य करते हुए जुलूस की भव्यता बढाई है। पुनः जुलुस भ्रमण कर बजरंगबली मंदिर पहुंचा। यहां आरती के पश्चात प्रसादी वितरण की गई। तत्पश्चात् जैन धर्मशाला में सामाजिक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें राष्ट्रीय नव नियुक्त अध्यक्ष बाबूलाल देवड़ा आलोट का सम्मान किया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठगण ,युवा जिन्होंने शिक्षा के साथ समाज की गरिमा बनाई, साथ ही समाज की दो होनहार महिला शारदा लोहार व सीमा लोहार जो पुलिस प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा दे रही है का सम्मान किया। साथ ही आयोजन में समाज हितेषी मुद्दों पर चर्चा की गई व समाजजनों ने अपने विचार व्यक्त किये।

आदिवासी भाई-बहन से मारपीट और छेड़खानी का आरोप

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन के भीकनगांव क्षेत्र के साईनाथ बेड़ी इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक आदिवासी युवती और उसके भाई के साथ मारपीट की गई। घटना 15 सितम्बर की शाम की बताई जा रही है। पीड़ित भाई-बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में युवती ने छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं।

पीड़िता ने बताया कि वह खेत से मिर्च तोड़कर घर लौट रही थी, तभी भारत और विक्रम नामक युवक मोटरसाइकिल से आए और उसे टक्कर मार दी। इसके बाद उन्होंने गाली-गलौज की और बाल पकड़कर मारपीट की। युवती का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। जब उसका भाई बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। हमले में भाई की पीठ पर गंभीर चोट आई। परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया और पुलिस अधीक्षक रविंद्र शर्मा को आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले में दूसरा पक्ष भी भीकनगांव थाने पहुंचा और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था।

भीकनगांव एसडीओपी राकेश मर्याने ने बताया कि यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम लग रही है। दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आदिवासी समाज ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

राशन दुकान की जगह बदलने से लोगों में आक्रोश

माही की गूंज, खंडवा।

मोरटक्का खेड़ीघाट, मोरटक्का स्टेशन और मालबेड़ी के ग्रामीणों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान को पाँच किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने पर आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने बिना पंचों से सलाह लिए यह निर्णय लिया, जिससे उन्हें राशन लाने में काफी परेशानी हो रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि ओंकारेश्वर फोरलेन राजमार्ग के कारण दुकान को हटाया जा रहा है, लेकिन इसे गाँव से पाँच किलोमीटर दूर मोरटक्का माफी के पुराने पंचायत भवन में संचालित किया जा रहा है। इससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को राशन लाने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनके पास आने-जाने का कोई साधन नहीं है। ग्रामीणों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मांधाता विधायक नारायण पटेल को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

ग्रामीणों की मांग है कि राशन की दुकान को या तो गाँव में ही रखा जाए या उनके परिवहन की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें राशन लाने में परेशानी न हो। मांधाता विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वे तीन दिनों के लिए गाँव में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलवाएंगे। वहीं सांसद ने कहा कि वे बैठकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे।

40 आरोपियों पर कार्रवाई, 322 लीटर शराब जब्त

माही की गूंज, खरगोन।

पुलिस अधीक्षक डॉ. रवींद्र शर्मा के निर्देश पर जिले के थानों और चौकियों में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई। जिले में 40 आरोपियों के खिलाफ 40 प्रकरण दर्ज किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें 39 प्रकरण धारा 34(1) और 1 प्रकरण धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। कार्रवाई में 118.62 लीटर अवैध देसी शराब, 20.06 लीटर विदेशी शराब और 184 लीटर हाथभट्टी शराब जब्त की गई। मौके पर लगभग 100 लीटर महुआ लहान भी नष्ट किया गया। जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 76,165 रुपये बताई गई है।

खरगोन में 2, मेनगांव में 2, ऊन में 5, बरूड में 1, भगवानपुरा में 6, गोगावां में 1, बड़वाह में 1, सनावद में 9, बेड़िया में 2, करही में 3, मंडलेश्वर में 2, महेश्वर में 7, कसरावद में 5 और बलकवाड़ा में 2 प्रकरण दर्ज किए गए।

पुलिस ने अवैध भैंस परिवहन पकड़ा

माही की गूंज, सेंधवा।

बिजासन चौकी पुलिस ने मंगलवार रात अवैध रूप से भैंसों का परिवहन कर महाराष्ट्र ले जा रहे एक आयशर वाहन को पकड़ा। इस कार्रवाई में 18 भैंसें जब्त की गईं और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

कार्रवाई को लेकर बुधवार को चौकी प्रभारी विनोद मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजासन चौकी के सामने नाकाबंदी की गई। इस दौरान वाहन (एमएच 18 वीजे़ड 7455) को रोका गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी भैंसों को क्रूरतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर वाहन में भरकर वध के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे थे। इस पर पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमीन (34) पिता साबीर खान (निवासी बालसमुद), हनीफ (45) पिता हाफिज खान (निवासी तलाई मोहल्ला, खरगोन) और साबीर (30) पिता सलीम खान (निवासी खसखसवाड़ी) के रूप में हुई है। सभी आरोपी खरगोन जिले के निवासी हैं।

बिजासन पुलिस की पांच दिनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अब तक कुल पांच वाहनों को पकड़ा गया है, जिनमें 90 भैंसें जब्त की जा चुकी हैं।

जेन-जी आंदोलन से चीनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश

एक अगस्त, 1955 को चीन और नेपाल के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे। इस साल इसके 70 साल पूरे होने पर क्या नेपाल में धूम-धड़ाके से समारोह मनाया जायेगा? चीनी सत्ता प्रतिष्ठान में जो उदासी है, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। 1950 के दशक के शुरुआती वर्षों में, नेपाल में चीन का प्रभाव बहुत कम था। एक नेपाली प्रधानमंत्री, केआई सिंह ने 1952 में कम्युनिस्टों के समर्थन से सरकार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, और असफल होने पर तिब्बत भाग गए। 30 नवम्बर, 1994 से 12 सितम्बर, 1995 के कालखंड में नेपाल के पहले कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी बने। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड', माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डॉ. बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली ऐसे नाम हैं, जो प्रकारांतर से पीएम की कुर्सी पर बैठे, और इनमें से कुछ रिपीट भी हुए।

सात दशकों में नेपाल इतना बदल गया, कि कोई भी सरकार कम्युनिस्टों के बग़ैर बने, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मगर, अशांति के समय चीन क्यों कर्तव्यविमूढ़ हो गया? क्या जानबूझकर ओली का तख्ता पलटने दिया गया? अक्तूबर 2022 तक होऊ यांगशी राजदूत थीं। कूटनीति से इतर उनका एक अलग ग्लैमर था। होऊ यांगशी इतनी एक्टिव, कि कम्युनिस्टों में फाड़ होने के बावजूद सबको समेट कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा देती थीं। 2018 में चीन ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) और माओवादी केंद्र के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकृत पार्टी में दो अध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई थी। दोनों अध्यक्षों को समान अधिकार दिए गए। सत्ता में दोनों गुटों को समान हिस्सा न मिलने के कारण 31 महीनों बाद पार्टी टूट गई। पहले विलय, फिर विघटन, यह सब देखते हुए चीन के लिए निराशाओं का सिलसिला जारी रहा।

आज बाहर से यही दिखता है, कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनने देने में चीन की कोई भूमिका नहीं थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नेपाल के संप्रभु निर्णयों के प्रति चीन के सम्मान पर ज़ोर दिया, और दोनों देशों के बीच 'सनातन मित्रता' को रेखांकित किया। ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणी में ज़ोर देकर कहा गया है, कि चीन और भारत के बीच संतुलन बनाना नेपाल के हित में है। यानी, नेपाल के कम्युनिस्ट भारत का डर दिखाकर चीन से जो माल-पत्तर समेटते थे, उसके दिन लद गए।

अगस्त, 2025 के पहले हफ्ते ओली पेइचिंग में ही थे, तब जेन-जी आंदोलन का धुआं उठने लगा था। लेकिन, ओली को चीनी सत्ता प्रतिष्ठान से यह चेतावनी क्यों नहीं मिली कि कुर्सी ख़तरे में है? ओली जब काठमांडो लौटे, सहयोगी नेपाली कांग्रेस के नेता चीन की राजधानी पहुंच गए। ऐसे में क्या आकलन करें? कैसे मानकर चलें, कि चीनी राजदूत चेन सोंग और मिलिटरी अताशे घाटी में चल रहे घटनाक्रमों से अनभिज्ञ थे? पिछले साल खुफियागिरी के लिए कुख्यात चीनी संस्था 'कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट' ने नेपाल के लिए 50,000 चीनी भाषा के पेशेवरों को नियुक्त किया था। सोचिये, सूचनाओं तक पहुंच में पेशेवर कैसे फेल हो सकते हैं?

चीन, 'बेल्ट रोड इनिशिएटिव' में विलम्ब को लेकर भी ओली से नाराज़ चल रहा था। 15 जुलाई, 2024 को ओली सत्ता में आये। 5 दिसंबर, 2024 को ओली ने चीन जाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर हस्ताक्षर किये। सात साल और सात महीने बाद, यदि बीआरआई को गति देने के लिए हस्ताक्षर होता है, समझ सकते हैं, चीन इस निकम्मेपन से कितना रुष्ट होगा।

चीन नेपाली कम्युनिस्ट लीडरशिप से अपेक्षा करता रहा, कि आपस में बर्तन बजाने के बावजूद, वो 'वन चाइना पॉलिसी' का समर्थन करते रहेंगे, और तिब्बती शरणार्थियों पर कड़ी निगरानी में कोताही नहीं बरतेंगे। ऐसा हुआ भी। 2008 में माओवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, चीन ने नेपाली सेना के साथ अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाया। पिछले साल ही चीन को एहसास हो गया, कि ओली और दाहाल के नेतृत्व में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के एकजुट होने की संभावना बहुत कम है। दोनों सत्ता के भूखे, निरंकुश, असहिष्णु, और अपने हितों के लिए सिद्धांतों को तोड़ने-मरोड़ने, फंड के पैसे डकार जाने की प्रवृत्ति वाले।

अंततः, चीन ने 'माइनस टू' फॉर्मूला शुरू किया, जिसके तहत ओली और दाहाल को अपनी-अपनी पार्टियों के नेतृत्व से मुक्त किया जाएगा। दोनों वाम नेताओं के खिलाफ असंतोष की आग भड़कती देखकर काठमांडू में लोगों का आकलन था, कि यह सब चीन के इशारे पर सम्भव है। सीपीएन (यूएमएल) के वरिष्ठ नेताओं ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, कि चीन चाहता है, पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ओली की जगह लें। सीपीएन (यूएमएल) के हवाले से कहा गया कि, 'विद्या देवी भंडारी को देश का व्यापक दौरा करने और अपनी यात्राओं के दौरान पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ-साथ आम लोगों से मिलने की सलाह दी गई है, ताकि उनके पक्ष में समर्थन जुटाया जा सके।' उन्होंने ऐसा किया भी। भंडारी की बढ़ती लोकप्रियता ओली के प्रभामंडल को निस्तेज करने लगी।

कहा जाता है कि नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन को माओवादी पार्टी का नेतृत्व संभालते चीन देखना चाहता है। पुन ने माओवादियों की सशस्त्र शाखा, 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ़ नेपाल' के मुख्य कमांडर के रूप में प्रचंड का स्थान लिया था, तब पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' पद से इस्तीफ़ा देकर मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होकर अगस्त 2008 में प्रधानमंत्री बने थे। पुन और भंडारी, जिनका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल एक साथ (अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2023 तक) था, एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं।

पुष्परंजन

मतलब ये कि नंद बहादुर पुन, माओवादी नेतृत्व संभालें और विद्या देवी एमाले की लीडरशिप। लेकिन पेइचिंग की योजना के सफल होने में कई दिक्कतें दरपेश हैं, जिनमें से प्रमुख हैं दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, जो निश्चित रूप से भंडारी और पुन के उदय को चुनौती देंगी। ठीक से देखा जाए, तो जेन-जी आंदोलन ने चीनी महत्वाकांक्षा और नेपाल में वामपंथ के प्रभाव पर अंकुश लगाया है, फिर भी ओली और दाहाल अपनी कुर्सी सहज रूप में किसी और को नहीं देने वाले।

चीन की चाल को समझते हुए, ओली ने पार्टी संविधान को ही पलट देने का दांव चला। नेपाल के गोदावरी में, 8 सितम्बर, 2025 को सीपीएन-यूएमएल का दूसरा संविधान सम्मेलन हुआ, जिसमें तय किया गया कि पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा नहीं होगी। इससे ओली के तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन, ओली को क्या मालूम था, कि अगले दिन उन्हें कुर्सी से जबरन बाहर किया जायेगा!

चक्रतीर्थ शमशान घाट पर जालसाजी

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर मंगलवार शाम को एक अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया। यहां कुछ युवक बिना शव लाए ही लकड़ी और कंडे खरीदने पहुंचे और मृतक के नाम से रसीद भी कटवा ली। लेकिन जब कर्मचारियों को शक हुआ और जांच की गई तो पूरा मामला जालसाजी का निकला। दरअसल, युवकों ने एक साल पहले मृत हो चुके अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यह साजिश रची थी।

बिना शव आए कटवाई रसीद, कर्मचारियों को हुआ शक

मंगलवार शाम चक्रतीर्थ कार्यालय पर तरुण पिता रेणुकुमार खत्री ड्यूटी पर थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी-कंडे की मांग की। उन्होंने मृतक का नाम लालचंद बताते हुए पूरी डिटेल रसीद में भरवा दी। लेकिन जब कर्मचारियों ने देखा कि दाह संस्कार के लिए केवल तीन-चार लोग ही आए हैं और शव भी उनके पास नहीं है, तो शक गहरा गया। पूछताछ में युवक घबरा गए और शवदाह गृह में जाकर जांच की तो वहां कोई शव नहीं मिला। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

गुम हो गई थी पुरानी रसीद, बनवाना चाहते थे नया प्रमाण पत्र

पुलिस पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनके पिता लालचंद की साल 2024 में मौत हो चुकी थी और अंतिम संस्कार चक्रतीर्थ पर ही किया गया था। लेकिन उस समय की रसीद गुम हो गई। अब उन्हें जमीन के दस्तावेज तैयार करवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत थी।

युवकों का कहना था कि उन्हें बताया गया था कि चक्रतीर्थ पर पुरानी तारीख की रसीद आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए यह रास्ता अपनाना पड़ा। युवक नीमच के रहने वाले हैं जबकि मृतक लालचंद उज्जैन में रहते थे।

साजिश की कोई जरूरत नहीं थी

चक्रतीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक प्रजापत ने कहा कि, यदि किसी की मृत्यु के बाद रसीद गुम हो जाती है तो परिजन शपथ पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत कर आसानी से उसी तारीख की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की जालसाजी या साजिश करने की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस ने शुरू की जांच

जीवाजीगंज थाना प्रभारी विवेक कनौडिया ने बताया कि, चक्रतीर्थ ट्रस्ट से शिकायत मिलने के बाद दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आवेदन पर जांच की जा रही है और जालसाजी के मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग, ग्रामीणों ने समस्याओं से कराया अवगत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा मंडल के प्रबंधक को आवेदन सौंपकर उदयगढ़ विकासखंड के ग्राम कोल्याबयडा में निर्मित रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि, स्टेशन का नाम वर्तमान में ÷डेकाकुण्ड÷ रखा गया है, जबकि स्टेशन कोल्याबयडा ग्राम में ही निर्मित है। ग्रामीणों की लंबे समय से यह मांग है कि स्टेशन का नाम बदलकर ÷कोल्याबयडा÷ किया जाए, ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहचान को उचित मान्यता मिल सके।

इसके साथ ही ग्रामीणों ने आवागमन की गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित कराया है। स्टेशन से डावर, मसानिया फलिया सहित आसपास के गांवों का आवागमन बाधित हो रहा है। इस स्थिति से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्रॉसिंग गेट की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

इसी प्रकार ग्राम बेहड़िया में रेलवे ब्रिज के पास पुलिया का निर्माण नहीं होने से बरसात में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। जिसके चलते चार स्कूल और दो आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

महेश पटेल ने कहा कि, रेलवे परियोजना के अंतर्गत किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें आज तक नियमानुसार पूरा मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। इससे ग्रामीणों में गहरा असंतोष है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए और की गई कार्यवाही से परिषद एवं ग्रामीणों को अवगत कराया जाए।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम भैंसोला से किया गया। जिसका ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण जिला चिकित्सालय आलीराजपुर प्रांगण में देखा एवं सुना गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में अतिथि कलेक?टर डॉ.अभय अरविंद बेडेकर रक्तदान कर कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रक्तदान हेतु आवाहन किया। यह जिले में उनका 20 वा रक्तदान है साथ ही आम नागरिकों से रक्तदान हेतु आग्रह किया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ देवेंद्र सुनहरे एवं सिविल सर्जन डॉ प्रकाश ढोके एवं डॉ प्रमेय रेवड़ियां द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़े के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित सीभी हितग्राहियों से अपील की जिले में लगने वाले जांच शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और उसका लाभ ले।इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रखर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष मक्कू परवाल, कैबिनेट मंत्री चौहान के विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता, रिंकेश तंवर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोंटू शाह ,डॉ. अमित अजनार, डॉ. अनिल कुमावत, जि.उप.विस्तार एवं माध्यम अधिकारी श्रीमती निर्मला चौहान सहित विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थिति थे।

किसान आंदोलन को लेकर पटेल की बड़ी बैठक

माही की गूंज, अलीराजपुर।

सोंडवा से शुरू हुए किसान आंदोलन की निरंतरता में पटेल फॉर्म हाउस बोरखड़ में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में बड़ी बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिले भर से किसान, नेता, सरपंच और जनपद सदस्य शामिल हुए।

बैठक में किसानों की प्रमुख मांगें उठाई गई। उमराली चोरी की ट्रेस कर दोषियों पर कार्रवाई, पुतला दहन प्रकरण में केस दर्ज, खराब फसल सर्वे और किसानों को मुआवजा, साथ ही सांठगांठ करने वाले पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई और फर्जी मुकदमे दर्ज करने वालों पर कार्यवाही की भी मांग उठी।

सभा को संबोधित करते हुए महेश पटेल ने कहा कि, कलेक्टर साहब के माध्यम से एसडीएम और नवागत एसपी से हमारी सार्थक चर्चा हुई है। हमारी प्रमुख जो मांगे हमने रखीं, उन पर अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आपकी हर मांग का समाधान किया जाएगा। एसडीएम ने खराब फसल सर्वे के आदेश जारी होने की जानकारी भी दी है। प्रशासन को एक मौका देना चाहिए ताकि हमारी समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान हो सके।

महेश पटेल ने चेतावनी दी कि, यदि लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाने वालों पर शीघ्र केस दर्ज नहीं हुआ, तो अलीराजपुर पुलिस थाने का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने भाजपा नेताओं नागर सिंह चौहान, अनिता चौहान और दिलीप चौहान पर भी आदिवासी समाज का अपमान करने, व्यापम घोटाले और राजवाड़ा कांड जैसी घटनाओं में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन ने जल्द और ठोस कार्रवाई नहीं की, तो सोंडवा से शुरू हुआ यह आंदोलन जिले से आगे प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा।

1000 ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रदेश के उज्जैन जिले में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के करीब 5000 किसान 1000 ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर गए। इन किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया है।

दरअसल, उज्जैन में लैंड पूलिंग योजना के तहत सरकार स्थायी सिटी बसाने की बात कर रही है। इसी के विरोध में भारतीय किसान संघ ने रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक न्याय परिसर से हुई। इस रैली में किसान सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना

यह विशाल ट्रैक्टर रैली चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, तीन बत्ती चौराहा से होते हुए कोठी पैलेस तक पहुंची। जहां कलेक्टर कार्यालय तक किसान पैदल पहुंचे और धरना दिया। फिर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को 15 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा। प्रदर्शन को लेकर भारतीय किसान संघ ने एक पेंपलेट भी जारी किया है। जिसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं को 15 बिंदुओं में लिखा गया है। इसमें मुख्य समस्या सिंहस्थ क्षेत्र की लैंड पूलिंग योजना को बताया गया है।

सीएम मोहन यादव को दे दी चेतावनी

किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर को यह बताने आए हैं कि सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन 1 वर्ष के लिए ले ली जाए। बाकी 11 वर्ष उन्हें खेती करने दिया जाए। इस भूमि पर पक्का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारे पास कई तरीके हैं। जिस-जिस सरकार ने किसानों की जमीन लेने की कोशिश की है उनका हाल देख सकते हैं। लैंड पूलिंग पर सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भोपाल में क्यों कह रहे हैं। वह यहां किसानों के बीच आकर कहें। यदि आज लैंड पूलिंग कैंसिल करते हैं तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे।

महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव शुरू

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति द्वारा उमा सांझी महोत्सव बुधवार से शुरू हो गया है जो 21 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत मंदिर परिवार के पुरोहित एवं पुजारीगण प्रतिदिन रंगोली सज्जा करेंगे और माण्डने बनाएंगे। भगवान महाकाल के विभिन्न मुखारविंद की झांकी सजाई जाएगी।

इस संबंध में मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि, महोत्सव के पहले दिन बुधवार को प्रातः शासकीय पुजारी पं.घनश्याम शर्मा द्वारा घट स्थापना की जाएगी। संध्या आरती पश्चात वसंत पूजा होगी। वहीं सायं साढ़े सात बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रीति देवले का लोक गायन और स्वाति उखले का लोक नृत्य समुह में प्रस्तुत होगा।

महोत्सव के तहत 22 सितंबर को कन्या भोज होगा वहीं 23 सितंबर को माता पार्वती रजत पालकी में विराजकर नगर भ्रमण करेंगी। सवारी महाकाल चौराहा, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, सराफा, छत्रीचौक से होते हुए मां शिप्रा के तट तक जाएगी। जवारे और संजा विसर्जन के बाद सवारी कहारवाड़ी, बक्षी बाजार होते हुए महाकालेश्वर मंदिर लौटेगी।

उल्लेखनीय है कि, महाकाल मंदिर में उमा-सांझी महोत्सव एक पांच दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी से शुरू होता है और लोक संस्कृति पर आधारित होता है। इसमें प्रतिदिन शाम की आरती के बाद लोक गायन, लोक वादन व लोक नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। महोत्सव के समापन पर उमा माता की सवारी निकाली जाती है।

राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का शुभारंभ

माही की गूंज, अलीराजपुर।

राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम भैंसोला से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया। जिसका उद्देश?य मोटापा नियंत्रण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, शिशु एवं बाल आहार प्रथाएँ, पुरुष सहभागिता को बढ़ाना, स्थानीय अनाज (मोटा अनाज) के उपयोग को बढ़ावा देना हैं। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया जिसमें हितग्राहियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण देखा गया साथ ही व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन जनसुनवाई कक्ष में किया गया। प्रतियोगिता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय मोटा अनाज एवं पोषण आहार के व्यंजन तैयार कर प्रदर्शनी में रखे गये।

इस दौरान कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर एवं जिला पंचायत सी.ई.ओ. प्रखर सिंह एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री मोनिका बघेल द्वारा व्यंजनों को अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात कलेक्टर डॉ .बेडकर ने बनाए गए व्यंजनों की सराहना करते हुए उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वयं स्वास्थ्य जांच करवाने एवं अन्य हितग्राहियों की भी स्वास्थ्य जाँच करवाने हेतु प्रेरित करने के लिये कहा। साथ ही डी.एस.सी. संस्था के प्रतिनिधियों में से जिला समन्वयक प्रशान्त द्वारा पोषण एवं मोटे अनाज के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों को व्यंजन की पोषकता एवं स्वाद के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किये गए। प्रतियोगिता में व्यंजन ÷उड़द के वड़े एवं पराठे÷ को प्रथम पुरस्कार, ÷गेहूँ चने की मीठी व नमकीन पुरी÷ को द्वितीय पुरस्कार एवं ÷ अंकुरित मूंग एवं चना÷ को तृतीय पुरस्कार वितरण किया गया।

स्वच्छता कार्यक्रम के साथ मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन

उदयगढ़ मंडल

ग्राम जामली

माही की गूंज, उदयगढ़। खलील मंसूरी

भारतीय जनता पार्टी उदयगढ़ मंडल द्वारा सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य व समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर ने देश के यश स्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा स्वच्छता, आत्मनिर्भरता व समाज उत्थान के कार्यों में नए आयाम को छू रहा है। उनके मार्गदर्शन में सेवा ही संगठन की आत्मा है और सेवा पखवाड़ा इस भावना को साकार करने के अवसर है। उन्होंने आगे बताया कि, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर वृक्षारोपण एवं कई प्रेरणादायक जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में आयोजित होंगे।

यह कार्यक्रम उदयगढ़ के प्राचीन शीतला माता मंदिर में स्वच्छता अभियानसे प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ्य नारी सशक्त परिवार, कार्यक्रम का शुभारंभ महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर सरपंच हीरा मुवेल एवं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुजराती द्वारा किया गया। तत्पश्चात मरीजों में फल वितरण एवं बुजुर्गों का सम्मान जैसे कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुजराती, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भावना नागर, महिला मोर्चा जिला महामंत्री कोकिला चौहान, उदयगढ़ सरपंच हीरा राजू मुवेल, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गौरव जैन, भाजपा नेता कमरू अजनार, मंडल महामंत्री हिमांशुजी सोनी प्रकाश जमरा, राहुल गहलोत, शुभम राठौड़ एवं पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम में भी मनाया जन्मदिन

माही की गूंज, जामली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ग्राम पंचायत जमाली, ग्राम छोटी जामली में मंडल उपाध्यक्ष रखब भूरिया बूथ मंत्री वाल सिंह सोलंकी बूथ क्रमांक 168 जामली बड़ी और बूथ क्रमांक 168 जामली बड़ी और बूथ क्रमांक 169 जामली छोटी के धार्मिक मंदिर बाबा देव जामली बड़ी में साफ सफाई कर पूजा पाठ किया गया। जिसमें मंडल महामंत्री भंवर सिंह अजनार, मंडल उपाध्यक्ष रखब भूरिया, पूर्व मंडल महामंत्री मुकेश अजनार, राव मोहनिया, सूअर सिंह मंडलोई, केरम अजनार, सुनील डावर, दिनेश सोलंकी, राकेश के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साफ-सफाई में अपना योगदान दिया।

अपना अभिनंदन...अभिनंदन...अभिनंदन... करवाते हुए सरपंच जी तो चल दिए

मंत्री ,सांसद भूली ब्लास्ट में दिवंगतो को, सीएम को भी याद दिलाना पड़ा

आखिर किस डर से परेशानी में डाल दिया नगरवासियों को प्रशासन ने

सभा के बाद मुख्यमंत्री के चले जाने के बाद तक लोगों के आवेदन सभा स्थल पर पड़े रहे।

रतलाम जिले में खेतों का दौरा, किसानों को लगाया गले।

माही की गूंज,पेटलावद।
राकेश गेहलोत

पेटलावद में मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारिया चल रही थी जो 12 सितंबर के आयोजन के साथ खत्म हुई। लगभग एक घंटे के कार्यक्रम में लिए करोड़ो रुपए फूके गए। उम्मीद थी की 12 सितंबर ब्लास्ट की तारीख पर पेटलावद को कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुख्यमंत्री महोदय ब्लास्ट में दिवंगतो को श्रद्धांजलि देने तक श्रद्धांजलि चौक तक नही पहुंचे। मंच से भाषण के दौरान मंत्री निर्मला भूरिया, सांसद अनिता नागरसिह ब्लास्ट पीड़ितो के लिए दो शब्द नहीं बोल पाए न ही अपनी ओर से शोक संवेदना प्रकट कर पाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जिनके श्रद्धांजलि चौक तक पहुंचने की पूरी तैयारी की लेकिन श्रद्धांजलि चौक तो ठीक भाषण में भी इस बड़ी त्रासदी को जगह नहीं मिली। भाषण समाप्त होने से पहले मंत्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री के कान में आकर इसकी जानकारी दी तब जाकर मुख्यमंत्री ने 12 सितम्बर 2015 को हुए ब्लास्ट में दिवंगत लोगो को श्रद्धांजलि अर्पित की।

पेटलावद सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव।

खुद ही जनता से बार-बार अभिनंदन करवाते रहे सीएम साहब

मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने भाषण के दौरान सबसे ज्यादा अपने लिये अभिनंदन शब्द का उपयोग करते सुनाई दिए। शासन की ओर से किसी योजना का बखान हो या किसी भी कार्य की घोषणा हर घोषणा के बाद अभिनंदन करो शब्द का उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री ने मंच से उन कार्यों की भी घोषणा कर दी जो की स्वीकृत होकर टेंडर की प्रक्रिया में भी चली गई। वही पेटलावद नगर को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली और वर्षो से चली आ रही सुव्यवस्थित बस स्टेशन की मांग पर फिर से घोषणा की गई। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से बस स्टेशन की घोषणा होती रही है लेकिन आज तक नगर परिषद को बस स्टेशन निर्माण के लिए जगह नहीं मिल सकी है जिससे बस स्टेशन का निर्माण हो सके। मंत्री भूरिया का फोकस भी इस बार रामा विकास खंड और उससे लगे झकनावदा की ओर ज्यादा रहा।

छावनी में बदला नगर, सीएम तक पहुंचना भगवान को छुने जैसा

किसी मुख्यमंत्री की सभा को लेकर इतना बड़ा ताम-झाम पहली बार देखा गया। मुख्यमंत्री के हेलीपेट से सभा स्थल तक पहुचने की व्यवस्था के साथ-साथ नगर के दूसरे हिस्सों को भी छावनी में बदल कर ज्यादातर मार्ग बंद कर दिए गए। जिससे कई लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। चार पहिया तो ठीक दो पहिया वाहन लेकर भी लोग नहीं निकल पाए जिसका सोशल मीडिया पर विरोध देखने को भी मिला। पूरे मामले को स्थानीय प्रशासन के उस डर से जोड़ा जा रहा है जो की किसानो और ब्लास्ट पीड़ितो से बना हुआ था कि कही से विरोध नही उठ खड़ा हो जिससे जिले में मची लापरवाही की पोल खुल जाए। मुख्यमंत्री तक कोन और कैसे और कहां पहुंचेगा सब पहले से प्रशासन ने तय किया था।

सभा में लेकर पहुंचे आवेदन, वही बिखरे नजर आए

कई लोग इस उम्मीद में आवेदन लेकर पहुंचे थे कि, उनकी शिकायत और मांग सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जायेगी लेकिन लोगो ने अपने आवेदन सभा स्थल पर तैनात कर्मचारियों के माध्यम से सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सभा स्थल पर आए आवेदन मुख्यमंत्री तक नही पहुंच सके और वही सभा स्थल पर पड़े नजर आए। वही एसडीएम द्वारा स्थानीय पत्रकारों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हुए कई पत्रकारों को पास जारी नही किए। जिससे सभा में मुख्यमंत्री के आने से पूर्व सभा स्थल पर मौजूद समस्त पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर बहार जाने की तैयारी कर ली लेकिन पुर्व में सीएम के आयोजन में दुध से जली की तर्ज पर कलेक्टर नेहा मीना के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ।

रतलाम जिले में पहुंचते ही बदलते-बदलते नजर आए मुख्यमंत्री

पेटलावद के आयोजन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा कार्यकर्म ने भाग लेने पहुंचे। सोशल मीडिया और मुख्यमंत्री के ऑफिशल सोशल साइड पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमे मुख्यमंत्री पूरी तरह बदले नजर आए। जहा एक और जिला प्रशासन ने पेटलावद में मुख्यमंत्री तक किसी आम जन मानस ,किसानो और अपनी मांगों को लेकर आए लोगो को उन तक पहुंचने तक नहीं दिया गया। वही सैलाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री किसानो के साथ खेत-खेत जाते नजर आए और कई किसानो ने उनका स्वागत हाथ में खराब हुई सोयाबीन की फसल देकर भी किया। तथा मुख्यमंत्री ने भी सहज मुलाकात किसानो से की व सांत्वना देते नजर आए। ऐसे में पेटलावद और रतलाम के दौरे के बीच मुख्यमंत्री के दो चेहरे नजर आए।

प्रधानमंत्री की सभा में जा रही एक बस ने बालक को रौंदा, मौत

निजी शैक्षणिक संस्थाओं ने पीएम की रैली के लिए दिए वाहन, परीक्षा रद्द कर बच्चों की कर दी छुट्टी

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसूरी

यूं तो मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सभाओं के लिए भीड़ एकत्रित करने के करीबी जिलों से सवारी वाहनों में लोगों को भर कर लाया और ले जाया जाना कोई खास या नई बात नहीं है। यह काम अक्सर राजनीतिक सभाओं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आयोजनों में होता ही है यह आम बात है, लेकिन जब इन सभाओं में भीड़ लाने ले जाने वाले वाहन ही आम लोगों को रौंदने लगे तो फिर उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए...? इस तरह की रैलियों में भीड़ भरकर जाने वाले वाहनों को खुली छूट प्रशासन की ओर से होती है। फिर चाहे वाहन का फिटनेस सही हो या न हो, चाहे सवारियां ठूंस-ठूंस कर भरी गई हो या फिर वाहन चालक का लायसेंस हो या ना हो, सवारी वाहन हो या लोडींग वाहन, नेताओं की रैलियों में जाने वाले इन वाहनों को प्रशासन और परिवहन विभाग खुले आम मौत का तांडव करने के लिए छोड़ देता है। ऐसा ही एक मामला जिले में सामने आया है, जिसमें एक मासूम की मौत हो चुकी है।

दरअसल 17 सितम्बर बुधवार को पड़ोसी जिले धार के ग्राम भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा हो रही थी। प्रधानमंत्री यहां पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल इंडस्टी ऐरिया का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। धार जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम आयोजन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। धार जिले के सीमावर्ती जिलों में भी इस आयोजन को लेकर खासी चहल-पहल प्रशासनिक अमलों में देखने को मिल रही थी। इस आयोजन को लेकर भाजपा अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी थी। इन्ही तैयारियों का एक हिस्सा था भीड़ एकत्रित करना और उसके लिए कई वाहनों से भीड़ को सभा स्थल तक पहुंचाना। इसी कड़ी में झाबुआ जिले की कई ग्राम पंचायतों से बसों व लोडींग वाहनो में भर कर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री मोदी की सभा स्थल भैंसोला ले जाया गया।

इसी तारतम्य में जिले के बोचका से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा के लिए ग्रामीणों को ले जा रही एक बस क्रमांक एमपी 45 पी 0271 ने माछलिया से मरगारूंडी जाने वाले रास्ते की एक पुलिया पर 7 वर्षिय बालक आदित्य पिता पूना वास्केल को रौंद दिया। हादसे की वजह समाचार लिखे जाने तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वाहन का कंडम होना बताया। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परीजन मिलकर गंभीर घायल बालक को कालीदेवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। गंभीर घायल बालक की स्थिति नाजूक होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान गंभीर घायल बालक आदित्य वास्केल ने अंतिम सांसे ली। घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया तो ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीण इस दुःखद घटना के बाद प्रशासन को कोसते हुए दिखाई दिए।

यह दुर्घटना इतनी हृदय विदारक थी कि, घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने घटना स्थल पहुंच कर सबसे पहले बस पर लगा प्रधानमंत्री की सभा का बैनर हटा दिया। पुलिस का इस तरह से बस से बैनर हटाना कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। क्या पुलिस प्रशासन इस मामले को छुपाना चाहता है या फिर इस कोशिश में है कि, कहीं यह हादसा प्रधानमंत्री की सभा से ना जुड़ जाए। हालांकि पुलिस ने वाहन जप्त कर विवेचना शुरू कर दी है।

परीक्षा रद्द, स्कूल की छुट्टी, क्योंकि बसें प्रधानमंत्री की रैली में

धार जिले के ग्राम भैंसोला में हो रही प्रधानमंत्री की सभा का असर झाबुआ जिले के स्कूली विद्यार्थियों और निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर भी देखने को मिला। दरअसल अभी वर्तमान समय में कई स्कूलों में त्रेमासिक परीक्षा हो रही है। कई शासकीय व गैर शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में परीक्षाएं चल रही है। वैसे तो इन परीक्षाओं में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं था लेकिन 17 सितम्बर को पड़ोसी जिले के ग्राम भैंसोला में प्रधानमंत्री की सभा ने इन विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों और शैक्षणिक संस्थाओं की रूटीन परीक्षाओं में व्यवधान डाल दिया। बच्चे जब 17 सितम्बर को अपने विद्यालय परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि, आज अवकाश घोषित कर दिया गया है और आज का परीक्षा पत्र आगे की दिनांको में लिया जाएगा। विद्यार्थियों ने जब इस का कारण जानने की कोशिश की तो स्कूल प्रबंधन से पता चला कि, आज पड़ोसी जिले के ग्राम भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा का आयोजन है और स्कूल की सारी बसें वहीं गई हुई है। जिसके चलते अंचल से आने वाले विद्यार्थियों का आना संभव नहीं था। इन सारे कारणों की वजह से 17 सितम्बर को होने वाला परीक्षा पत्र अब आगे की दिनांकों में होगा। हालांकि कई शैक्षणिक संस्थाओं ने इसकी सूचना एक दिन पूर्व ही सोशल मीडिया के माध्यम से परीक्षार्थियों व उनके पालकों को दे दी थी, लेकिन कई छात्र सूचना के अभाव में विद्यालय पहुंचे उसके बाद ही उन्हे इस बात का पता चला।

विद्यार्थियों के अनुसार हमने आज होने वाले परीक्षा पत्र की पूरी तैयारी देर रात तक की थी और सुबह भी 4 बजे से उठकर पढ़ाई कर रहे है। मगर स्कूल पहुंचने पर पता चला कि, आज छुट्टी है और आज का पेपर सबसे आखिरी में होगा। जब विद्यार्थियों से सूचना के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि, पिछले कुछ दिनों से परीक्षाएं चल रही है और हम लगातार पढ़ाई करने में व्यस्त है, जिसके चलते सोशल मीडिया या मोबाईल का उपयोग नहीं कर रहे है। जिसके कारण हमें विद्यालय द्वारा दी गई सूचना का पता नहीं चल सका। अचानक पेपर रद्द होने और छुट्टी होने से थोड़ा बुरा लग रहा है। हम पूरी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब बिना पेपर दिए ही अगले पेपर की तैयारी करेंगे। क्योंकि आज होने वाला परीक्षा अब सबसे आखिरी में होगी।

ये कैसा कन्यादान...? कन्या पहुंच गई ससुराल और दान अटक गया सरकारी गलियारों में

अब कन्या से बनी बहु जो हो रही परेशान और लगा रही सरकारी दफ्तरों के फैरे

अफसरशाही के चलते आयोजन के 6 माह बाद भी मुख्यमंत्री का दावा झूठा ही साबित हो रहा है

माही की गूंज, झाबुआ।

लगभग 6 माह पूर्व जिला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामुहिक विवाह आयोजन की योजना बनाई। यह आयोजन जिले के हर ब्लॉक में आयोजित होना था, लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिले में दौरा तय हो गया। प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर चौका लगाने के चक्कर में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम को तमाम ब्लॉकों से उठाकर जिला मुख्यालय पर एक ही जगह संग्रहित कर दिया। मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम के बाद जिला प्रशासन ने आनन-फानन में अपने कार्यक्रम की रूपरेखा में तब्दीली की और जिला मुख्यालय के समीप गोपालपुरा हवाई पट्टी पर इस आयोजन को रखा गया। अधिकारियों की मंशा सिर्फ इतनी थी कि, इस आयोजन के बाद मुख्यमंत्री उनकी पीठ थपथपा दें और उनके सर्विस रिकार्ड में एक और उपलब्धि शामिल हो जाए। इस आयोजन में जिले के सभी ब्लॉकों से 1917 जोड़े मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शामिल हुए। इस योजना के तहत हर कन्या को 49 हजार रूपए कन्यादान के रूप में सरकार द्वारा दिए जाते है। जिला मुख्यालय पर हुआ यह आयोजन सफल रहा। मुख्य अतिथि के रूप में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस आयोजन में शामिल हुए और नवविवाहितों को आशिर्वाद दिया। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह आश्वासन तमाम नवविवाहित कन्याओं को दिया था कि, आपके घर पहुंचने के पहले आपके खाते में यह कन्यादान की राशि जमा हो जाएगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी विवाहित जोड़े अपने-अपने घर पहुंच गए और पुरी सामाजिक रस्म अदायगी के साथ कु. कन्या से बहु बन गई तथा कई नव विवाहिता सोभाग्य से गर्भवती भी हो गई होगी। लेकिन अब तक भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सभी विवाहिताओं को कन्यादान की राशि नहीं पहुंच पाई। आयोजन के कुछ दिनों बाद 1917 जोड़ों में से 1317 जोड़ों को यह राशि बैंक खाते में पहुंच गई, लेकिन बचे हुए 600 सौ से ज्यादा जोड़ों को आज दिनांक तक यह राशि नसीब नहीं हुई है। इन 600 नवविवाहिताओं की कुल राशि लगभग 3 करोड़ है। आयोजन स्थल पर जिस तरह की घोषणा हुई और जिस तरह के जिला प्रशासन के तेवर नजर आए वे भी किसी से छुपे नहीं है। व्यवस्थाओं की कमी और कई मीडिया कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी का दंश प्रशासन के आला अधिकारियों को झेलना पड़ा था। उस समय कलेक्टर और एसपी के तेवर भी गुंडा तत्वों की तरह हो गए थे। मीडिया कर्मियों को खुलेआम धमकियां दी गई और कलेक्टर, एसपी ने निगरानी के साथ-साथ यह कहा था कि, शहर के हर कौने पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है, कौन क्या करता है हमे सब पता है। हर किसी के ईशुस् पता है। इसके बाद जिला प्रशासन के दोनों ही अधिकारियों को पत्रकारों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों के हुए धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए अधिकारियों ने खूब मान मनोवल कर हाथ जोड़े थे। हर पत्रकार के पीछे एक अधिकारी लगाया गया था।

खैर जो भी हो लेकिन भारतीय परम्परा में कन्यादान का अपना अलग ही महत्व है। यह एक ऐसी परम्परा है जो विवाह आयोजन की अंतिम रस्म और महत्वपूर्ण परम्परा होती है। हिन्दु संस्कृति में कन्यादान होने का मतलब यह है कि, विदाई से पहले ही कन्या की झोली में कन्यादान दे दिया जाता है। मगर राजनीतिक हथकंडों और बेलगाम अफसर शाही ने अपनी स्वार्थ सिद्धी में अंधा होकर इस हिन्दु संस्कृति की खुले आम धज्जियां उड़ाने का दुःसाहस किया है। 6 माह पहले ब्याही कन्याओं का कन्यादान अब तक उनके पास नहीं पहुंचा हैं। अब अपने ससुराल पहुंच चूकी कन्याएं कन्यादान की राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के फैरे लगा रही है। बिना कन्यादान के कन्या की विदाई और उसका ससुराल पहुंच जाना सही तो नहीं कहा जा सकता।

मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई में आई कई नवविवाहिताओं ने आवेदन देकर कन्यादान राशि की मांग की है। इसे शगुन कहें या अपशगुन...? लेकिन अफसर शाही है कि अब भी टाल मटोल ही कर रही है। बताया जाता है कि, जिन 600 कन्याओं को विवाह कन्यादान की राशि नहीं मिली है उनमें पूरे के पूरे दो ब्लॉक की कन्याएं शामिल है। पेटलावद ब्लॉक में पहले ही यह मामला उजागर होकर तूल पकड़ चुका है, तो राणापुर ब्लॉक के नवविवाहित जोड़े भी अब अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंच चुके है। मगर अब तक भी स्थिति इनके साथ ढाक के तीन पात ही साबित हो रही है। कन्यादान राशि में लेट-लतीफी का कारण यह बताया जा रहा है कि, जिन दो ब्लॉकों की 600 कन्याओं को यह राशि नहीं मिली है, उन ब्लॉकों के जनपद सीईओ का तबादला हो चुका है। नए आए सीईओ जब तक प्रक्रिया को पूरा करते बजट खत्म हो चुका था।

अधिकारियों का इसमें कहना है कि, बजट खत्म हो गया था इसलिए राशि नहीं पहुंच पाई, जल्द ही बजट आएगा और आप लोगों के खातों में कन्यादान की राशि पहुंचा दी जाएगी।

अब सवाल यह उठ रहा है कि, जिस योजना को जिला प्रशासन ने ब्लॉक स्तर पर आयोजित करना तय किया था वह सिर्फ मुख्यमंत्री के आने की वजह से जिला मुख्यालय पर क्यों किया गया...? या फिर जिन लोगों की विवाह कन्यादान की राशि अटकी है कहीं ऐसा तो नहीं कि, वह राशि प्रशासन व जिले के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आयोजन पर उड़ा दी। क्योंकि यह संभव ही नहीं कि, ब्लॉक स्तर पर होने वाले आयोजनों पर खर्च होने वाली राशि का अंदाजा प्रशासन को नहीं होगा। जो विवाह आयोजन ब्लॉक स्तर पर होना थे उसका बजट प्रशासन के पास होने के बाद ही कार्यक्रम की योजना तैयार की गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि, अचानक से मुख्यमंत्री का दौरा तय हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धी और अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में जिला मुख्यालय पर बड़ा आयोजन कर डाला और बजट से अधिक राशि इस आयोजन पर खर्च हो गई। बजट से अधिक खर्च हुई राशि की भरपाई कहीं कन्यादान राशि से तो नहीं कर ली गई? अगर ऐसा हुआ है तो फिर प्रशासन और उसमें बैठे आला अधिकारियों ने बहुत ही बड़ा पाप कर डाला है। शायद अगर मुख्यमंत्री का दौरा इस आयोजन के दौरान ना होता और यह आयोजन प्रशासन की पूर्व योजना के अनुसार ब्लॉक स्तर पर ही आयोजित होता तो शायद इन भटकती 600 विवाहिताओं को भी अपने विवाह में मिलने वाली कन्यादान राशि मिल गई होती। यह बात भी कहीं से हजम नहीं होती की बजट खत्म हो गया है या बजट आएगा तो कन्यादान की राशि मिलेगी। क्यों यह बात फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती नजर आती है कि, आखिर बजट नहीं था तो फिर मुख्यमंत्री के सामने इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? जब कन्यादान की राशि देने का बजट नहीं था तो फिर इतनी संख्या में जोड़ों को क्यों बुलाया गया? कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि, जिला प्रशासन ने इस आयोजन को करने में जितनी चादर थी उससे ज्यादा पैर पसार दिए। जिसके चलते आयोजन में मुख्यमंत्री की घोषणा जिसमें उन्होने नवविवाहितों के घर पहुंचने से पहले राशि उनके खातों में पहुंचने का दावा किया था जो झूठा साबित हुआ। और आज 6 माह बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का यह दावा झूठा ही साबित हो रहा है।

अब इन 600 नवविवाहितो को डर सता रहा है कि, उनके विवाह में दी गई कन्यादान की राशि उन्हे मिलेगी भी या नहीं? कहीं प्रशासनिक तंत्र में बैठे बागड़ बिल्ले उनकी कन्यादान की राशि हजम तो नहीं कर जाएंगे। इनके मन में उठने वाली यह शंकाए वाजिब भी है क्योंकि जिले में प्रशासनिक तंत्र की स्थिति किसी से दबी-छुपी नहीं है। मगर यह भी तय है कि, अगर राशि इनको नही मिली तो वह किसी और को भी हजम नहीं होगी। चाहे फिर वह कोई अधिकारी हो, अफसर हो या फिर सरकार... भुगतना तो पड़ेगा ही...।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422